वर्ष 13 • अंक 31 • 18 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

मंगलवार 24 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 4

ग्राहकों को समय से पहले ईपीएफओ से पेंशन!

आदित्य पुरी पृष्ठ 2

पुरी के उत्तराधिकारी का फैसला अप्रैल तक

डॉलर रु. 76.30 ▲ 01.10 रुपये | यूरो रु. 81.40 ▲ 90 पैसे | सोना (10ग्राम) रु. 40556 ▼ 613 रुपये | सेंसेक्स 25981.20 ▼ 3934.70 | निफ्टी 7610.30 ▼ 1135.20 | निफ्टी फ्यूचर्स 7603.60 ▼ 06.60 | ब्रेंट क्रूड 25.50 डॉलर ▲ 0.20 डॉलर

एक नज़र

वित्त विधेयक को मंजूरी संसद सत्र स्थगित

संसद के निचले सदन लोकसभा में सोमवार को वित्त विधेयक पारित हो गया। इसके साथ ही सरकार को पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर तक वृद्धि करने की मंजूरी भी मिल गई। कोरोनावायरस के संकट से पैदा हालात के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में वित्त विधेयक-2020 बिना चर्चा के पारित हो गया। पृष्ठ 4

दिल्ली में 65,000 करोड़ रुपये का बजट पेश

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 65,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। सोमवार को राज्य विधानसभा में पेश बजट में शिक्षा एवं स्थास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में शिक्षा के लिए सर्वाधिक 15,815 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह रकम बजट का 24.33 प्रतिशत है। पृष्ठ 4

शिवराज ने ली मप्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ

शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सोमवार देर शाम अपना नेता चुन लिया। उसके बाद देर रात राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें रमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उन्होंने चौथी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

फेडरल रिजर्व ने बढ़ाया उधारी कार्यक्रम का दायरा

कोरोनावायरस से परेशान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने सोमवार को कहा कि वह असीमित मात्रा में बॉन्ड खरीदने के लिए तैयार है। बाजार ने पर्याप्त मात्रा में नकदी बहाल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने अपने उधारी कार्यक्रम का दायरा बढ़ाने की घोषणा की और इसमें खास तरह के कॉर्पोरेट और म्युनिसिपल बॉन्ड को भी शामिल कर लिया।

तेजड़ियों पर बंदी की मार, हांफ रहा बाजार

भारतीय बाजार का प्रदर्शन सबसे खराब, 13 फीसदी लुढ़के सूचकांक

बाजार पूंजीकरण में 14 लाख करोड़ रुपये की चपत, वित्तीय शेयरों पर बड़ी मार

समी मोडक
मुंबई, 23 मार्च

बेंचमार्क निफ्टी 50 सूचकांक में आज 13 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट आई। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों से देश की अर्थव्यवस्था एक तरह से ठप हो गई है जिससे निवेशकों में दहशत का माहौल है। बिकवाली का यह आलम था कि एक ही दिन में निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए। पिछले सप्ताहांत केंद्र और कई राज्य सरकारों ने बंदी की घोषणा की थी जिससे अर्थव्यवस्था अचानक ठहर गई।

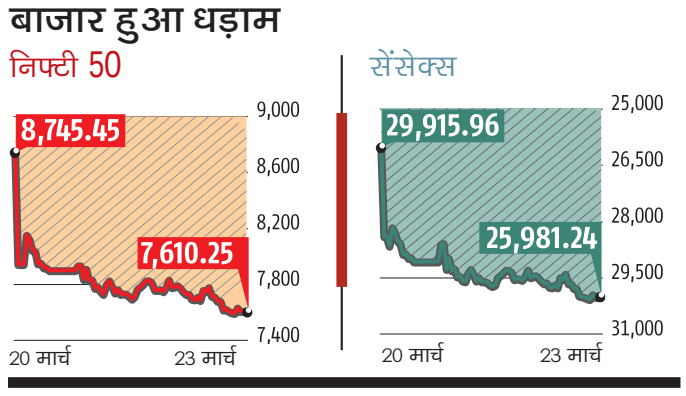

बाजार के जानकारों के मुताबिक निवेशकों को आशंका है कि अगर कोरोनावायरस को काबू में नहीं किया गया तो इससे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

इन्हीं आशंकाओं का नतीजा था कि निफ्टी 1,135 अंक की गिरावट के साथ 7,610 पर बंद हुआ जो 8 अप्रैल, 2016 के बाद इसका न्यूनतम स्तर है। अंक और प्रतिशत दोनों लिहाज से निफ्टी की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। सेंसेक्स भी 3,935 अंक की गिरावट के साथ 25,981 पर बंद हुआ जो 26 दिसंबर, 2016 के बाद इसका न्यूनतम स्तर है। निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक और स्मॉलकैप 100 सूचकांक करीब 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए।

बाजार खुलने के साथ सेंसेक्स ने 10 फीसदी का गोता लगाया जिसके कारण करीब एक घंटे तक कारोबार रोकना पड़ा। इससे पहले जब बाजारों ने लोअर सर्किट को छुआ था तो सूचकांक दोबारा कारोबार शुरू होने पर 16 फीसदी चढ़ा था लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और बेंचमार्क सूचकांकों को कोई राहत नहीं मिली और वे दिन के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए।

टौरस म्युचुअल फंड में इक्विटीज के प्रमुख प्रसन्न पाठक ने कहा, 'हमारा मानना है कि यह दौर यहीं थमने वाला नहीं है। इसे पटरी पर लौटने में लंबा समय लगेगा और इस दौरान अर्थव्यवस्था और निवेशकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोरोनावायरस के प्रकोप से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती का दौर था। निवेशकों की सारी उम्मीदें मौद्रिक और वित्तीय उपायों पर टिकी हैं।'

दुनिया के अधिकांश बाजारों में भी गिरावट देखी गई लेकिन बड़े बाजारों में केवल भारत में ही दो अंक की गिरावट आई। कुछ जानकारों ने कहा कि बाजारों को बंद करने की आशंका ने भी आग में घी का काम किया। मार्च में अब तक सेंसेक्स और निफ्टी में 32 फीसदी की गिरावट आ चुकी है।

फोटो : कमलेश पेढणेकर

ओएमओ तय तारीख से पहले

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय प्रणाली में अधिक तरलता लाने के लिए दो किस्तों में एक लाख करोड़ रुपये की सावधि रीपो प्रावधान की घोषणा की है। इसके साथ ही बैंकिंग नियामक ने अगले सप्ताह प्रस्तावित द्वितीयक बॉन्ड खरीद योजना को भी पहले खिसका दिया है। आरबीआई ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि रीपो प्रावधान से बैंकिंग प्रणाली में किसी भी तरह की प्रतिरोधात्मक तरलता जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। लेकिन उसी के साथ प्रणाली में अधिक डॉलर डालने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए विशेष अदला-बदली कदम का स्वागत बेमन से किया गया। आरबीआई ने बाजार में 2 अरब डॉलर बेचने का फैसला किया लेकिन बैंकों ने इनमें से केवल 1.53 अरब डॉलर के लिए ही बोली लगाई।

रुपया भी गया 76 के पार

सोमवार को अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से फिसला। कोरोना को लेकर दुनिया में बची उथलपुथल के कारण रुपया पहली बार 76 के पार चला गया गया और 76.20 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान रुपया 76.30 के स्तर पर पहुंच गया था। मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि आरबीआई ने रुपया 76 से नीचे रखने के लिए हस्तक्षेप जरूर किया था, लेकिन बाद में बाजार में दबाव और बढ़ने से मामला हाथ से निकल गया। डॉलर के मुकाबले दूसरे देशों की मुद्राओं में भी 0.5-1.0 प्रतिशत तक गिरावट देखी गई। मुद्रा कारोबारी फिलहाल यह कहने से बच रहे हैं कि रुपया कहां जाकर ठहरेगा, लेकिन इनमें कुछ का मानना है कि फिलहाल शेयर एक सीमा से अधिक लुढ़क गए हैं और आगे और गिरावट की गुंजाइश शायद न हो, जिससे रुपये को थोड़ा समर्थन मिलना चाहिए।

देश भर में घरेलू उड़ानें बंद महाराष्ट्र और पंजाब में कर्फ्यू

बीएस संवाददाता/एजेंसियां
मुंबई/नई दिल्ली, 23 मार्च

- **24 मार्च की मध्यरात्रि से घरेलू उड़ानों पर रोक**
- **देश के 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में पूरी तरह लॉकडाउन**

कोरोनावायरस के संक्रमण में तेजी की आशंका देखकर महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगा दिया गया है तथा देश के 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इनके अलावा छह राज्यों में कुछ जिलों को लॉकडाउन किया गया है।

संक्रमण फैलने से रोकने के लिए रेलगाड़ियां पहले ही बंद की जा चुकी थीं, आज घरेलू यात्री विमानों का परिचालन बंद करने का फैसला भी कर लिया गया। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि 25 मार्च से देश में कोई भी घरेलू विमान उड़ान नहीं भरेगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रविवार से रोकी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने बताया कि 24 मार्च की मध्यरात्रि से सभी घरेलू व्यावसायिक विमानन कंपनियों का परिचालन बंद हो जाएगा। लेकिन मालवाहक विमानों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। रेलगाड़ियां 31 मार्च तक के लिए बंद की जा चुकी हैं।

इस बीच आज कोरोना संक्रमण के 55 नए मामले सामने आने के बाद देश भर में कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 468 हो गई। दुनिया में करीब 3.5 लाख लोग इससे संक्रमित हैं और 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इधर देश के 75 जिलों में आज से लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी और निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई थी। इसके बावजूद कई इलाकों में लोग घरों से बाहर नजर आए, जिसके कारण केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को आदेश कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया कि लॉकडाउन को कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वे नियमों का सख्ती से पालन कराएं।

पंजाब में भी लोगों ने निषेधाज्ञा का पालन नहीं किया और मामलों में इजाफा देखा गया। इसके बाद आज सरकार ने पूरे राज्य में कर्फ्यू लगा दिया। (शेष पृष्ठ 18 पर)

व्यापार गोष्ठी

मौजूदा हालात में कैसे थमे आर्थिक गिरावट?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या रुपये में कमजोरी से सरकारी खजाने पर पड़ेगा असर

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या शटडाउन से कोरोना पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद?

हां	71.43%
नहीं	28.57%

श्रमिकों को मिले नकद, उद्योग को प्रोत्साहन

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 23 मार्च

- **प्रधानमंत्री के साथ भारतीय उद्योग जगत ने की बैठक**
- **आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिले 5,000 रुपये नकद**
- **उद्योगों ने मौजूदा स्थिति छंटनी नहीं करने का दिया भरोसा**

कोरोनावायरस के बढ़ते संकट और देश भर में कारखानों एवं दफ्तरों के बंद होने से सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मौद्रिक सहायता बढ़ाने और घरेलू उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया कराने की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में भारतीय उद्योग जगत ने ये बातें बताईं।

देश के 75 जिलों को लॉकडाउन करने के बाद मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये औद्योगिक उत्पादन में तेजी से आ रही गिरावट के लिए संभावित समाधान तलाशने पर उद्योग के साथ आज चर्चा की। बैठक में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की अध्यक्ष संगीता रेड्डी और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर भी शामिल थे। अधिकांश उद्योगपतियों की राय थी कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके को तत्काल नकद प्रत्यक्ष अंतरण करने की जरूरत है।

सूत्रों ने कहा कि दोनों उद्योग संगठनों कामगारों और 5 लाख रुपये से कम आय वाले लोगों को 5,000 रुपये नकद देने के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को एकमुश्त 10,000 रुपये देने की मांग की। प्रधानमंत्री ने उद्योग संगठनों की सिफारिशों को गंभीरता से सुना और प्रस्तावित नकद अंतरण की विस्तृत योजना के बारे में जानने की इच्छा जताई ताकि उपभोक्ता मांग में इजाफा हो सके।

इसके साथ ही उद्योग ने ऋण प्रावधानों में ढील देने तथा नकदी बढ़ाने के उपाय करने की भी मांग की। किर्लोस्कर ने कहा, 'सभी कर्जदारों को सभी तरह के कर्ज के भुगतान की बाध्यता को पूरा करने के लिए तीन महीने की रियायत देनी चाहिए और मौजूदा अवधि में कर्ज वसूली नहीं करनी चाहिए। सीआईआई ने इस बात पर जोर दिया कि सभी क्षेत्र के उद्योगों के लिए कर्ज की सुविधा बढ़ाने की तत्काल जरूरत है और सरकार को अगले तीन महीने के लिए ब्याज तथा मूलधन के स्थगन के उपाय तलाशने चाहिए।' उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता कारोनावायरस के प्रसार को रोकने तथा जल्द से जल्द संक्रमण के नए मामले घटाने की होनी चाहिए। सीआईआई ने डॉलर तरलता स्वैप की भी मांग की।

फिक्की का कहना है कि सरकार को राजकोषीय घाटे में 200 आधार अंक इजाफे का बोझ वहन करना चाहिए। फिक्की के अनुसार इसे वित्तीय प्रणाली में 4 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी आएगी। संगीता रेड्डी ने कहा, '16 मार्च 2016 से किसी ऋण को गैर-निष्पादित आस्तियों के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही मानक ऋणों का भुगतान कम से कम दो तिमाहियों के लिए टाल दिया जाना चाहिए। बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही वाणिज्यिक पत्रों एवं कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए भी पर्याप्त नकदी रखी जानी चाहिए।'

(शेष पृष्ठ 2 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

ऐक्सिस बैंक

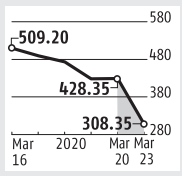

मार्च 2016 के बाद पहली बार बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रु. से नीचे

₹ 428.40 पिछला बंद भाव
₹ 308.40 आज का बंद भाव
▼ 28.00 %

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा फाइनैंशियल सर्विसेज

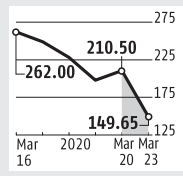

वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में सबसे ज्यादा टूटने वाला

₹ 210.50 पिछला बंद भाव
₹ 149.70 आज का बंद भाव
▼ 28.90 %

जेएसडब्ल्यू स्टील

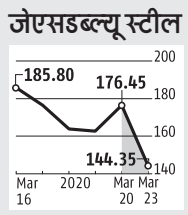

स्टील कीमतों में उम्मीद से सुस्त सुधार पर केयर ने रेटिंग में किया संशोधन

₹ 176.50 पिछला बंद भाव
₹ 144.40 आज का बंद भाव
▼ 22.20 %

मारुति सुजूकी इंडिया

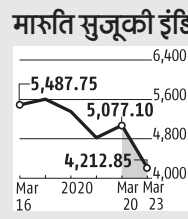

कोरोनावायरस के कारण भारत में उत्पादन रोका

₹ 5,077.10 पिछला बंद भाव
₹ 4,212.85 आज का बंद भाव
▼ 17.00 %

आईआरसीटीसी

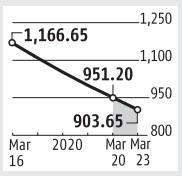

कोरोना के कारण पर्यटन उद्योग में नरमी से 4 हफ्ते में 53 फीसदी टूटा

₹ 951.20 पिछला बंद भाव
₹ 903.70 आज का बंद भाव
▼ 5.00 %

संक्षेप में

किया मोटर्स, बीएमडब्ल्यू, रेनो ने बंद किया उत्पादन

किया मोटर्स, लक्जरी कार विनिर्माता बीएमडब्ल्यू और फ्रांस की वाहन कंपनी रेनो ने सोमवार को कोरोनोवायरस महामारी के कारण अपने संबंधित संयंत्रों में अस्थायी रूप से उत्पादन गतिविधियों को बंद करने की घोषणा की। *एजेंसियां*

बजाज ऑटो के विनिर्माण संयंत्र भी फिलहाल बंद

बजाज ऑटो ने सोमवार को कहा कि उसने कोरोनोवायरस के प्रकोप के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा घोषित उपायों के मद्देनजर अपने विनिर्माण संयंत्रों में कामकाज को फिलहाल बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा कि उसने अपने कार्यालयों के कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया है जबकि कर्मचारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्राओं और अन्य बैठकों को रद्द कर दिया गया है। *एजेंसियां*

सुजूकी के गुजरात संयंत्र में उत्पादन बंद

मारुति सुजूकी इंडिया (एमएसआई) ने सोमवार को कहा कि सुजूकी मोटर गुजरात ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर अपने गुजरात संयंत्र में उत्पादन को फिलहाल निलंबित कर दिया है। एसएमजी यानी सुजूकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड मारुति सुजूकी के लिए अनुबंध के आधार पर कारों का निर्माण करती है। *एजेंसियां*

लॉकडाउन के कारण कंपनियों के समक्ष चुनौती

उत्पादन बरकरार रखने के लिए संघर्ष

विवेट सुजन पिंटो और टीई नरसिम्हन
मुंबई/चेन्नई, 23 मार्च

- बफर स्टॉक तैयार करने और कर्मचारियों को बारी-बारी से बुलाने पर कंपनियों का जोर
- राज्य सरकारों ने रविवार और सोमवार को किराने की वस्तुओं और स्टेपल्स बनाने वालों को विनिर्माताओं की अपनी सूची से छूट दी
- इससे आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो

कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप से निपटने के लिए देश भर में शहरों को लॉकडाउन करना एक अप्रत्याशित परिस्थिति है लेकिन इससे आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण पर भारी असर पड़ा है। डाबर ने सोमवार को कहा कि उसने 31 माच4 तक अस्थायी तौर पर ज्यादातर उत्पादों का उत्पादन निलंबित कर दिया है, जिसमें आयुर्वेद दवाएं, च्यवनप्राश, हैंड सैनिटाइजर शामिल नहीं है।

राज्य सरकारों ने रविवार और सोमवार को किराने की वस्तुओं और स्टेपल्स बनाने वालों को विनिर्माताओं की अपनी सूची से छूट दी ताकि आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन कई जगहों पर धारा 144 को सख्ती से लागू किए जाने के कारण लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है। ऐसे में रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं (एफएमसीजी) बनाने वाली कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारियों को अपनी फैक्टरियों को चालू रखना एक बड़ी चुनौती दिख रही है।

कई इकाइयों में कर्मचारियों की संख्या घटकर 25 फीसदी रह गई है। कुछ इकाइयों में तो कर्मचारियों की उपस्थिति केवल 15 फीसदी रह गई है। जबकि कुछ अन्य लोगों ने मजबूरन अपनी इकाइयों को अस्थायी तौर पर केवल इसलिए बंद दिया है क्योंकि परिवहन व्यवस्था बाधित होने के कारण श्रमिक काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं।

डाबर इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा, 'लॉकडाउन के कारण हमारे संयंत्रों में काफी कम कर्मचारी मौजूद हैं।' उन्होंने कहा, 'गाजियाबाद, अलवर और कोलकाता में कुछ इकाइयां बंद हैं। यह एक कठिन समय है। लेकिन हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमारे उन लोगों की सुरक्षा है जो काम पर आ रहे हैं। कर्मचारियों को समूह में बांटकर बारी-बारी से बुलाया जा रहा है।'

ज्योति लेबोरेटरीज की प्रबंध निदेशक एमआर ज्योति ने कहा कि सोमवार को उनकी कंपनी की कुल 25 फैक्टरियों में से केवल 5 फैक्टरियों का ही परिचालन हो रहा है। उन्होंने कहा, 'हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी बीस इकाइयां कैसे चलेंगी। वर्तमान में स्थिति काफी अप्रत्याशित है। इसलिए अभी हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे परिस्थिति कैसी रहती है।'

मौजूदा अनिश्चितता के माहौल और लॉकडाउन को मार्च से अप्रैल के पहले सप्ताह तक बढ़ाए जाने की आशंका को देखते हुए सीईओ ने कहा कि फैक्टरियों में कर्मचारियों के बीच भ्रम और घबराहट को दूर करने के लिए वह अपने लोगों के साथ लगातार बातचीत कर रही हैं।

गोदरेज कंज्यूमर के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी विवेक गंभीर ने कहा, 'हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी टीम के सदस्यों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं ताकि बाजार में हमारे उत्पादों की आपूर्ति बरकरार रहे। हमारी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि सैनिटाइजर, हैंडवॉश और साबुन जैसी अधिक मांग वाली वस्तुओं की विभिन्न चैनलों में पर्याप्त आपूर्ति की जाए।'

हिंदुस्तान यूनिलीवर, जीसीपीएल और आईटीसी सहित स्वच्छता उत्पाद बनाने वाली अधिकतर कंपनियां इन उत्पादों की मांग बढ़ने पर उत्पादन और वितरण में तेजी ला रही हैं। इसके लिए वे स्थानीय अधिकारियों से बात भी कर रही हैं कि वे अपने संयंत्रों में उत्पादन जारी रखने के लिए इन्वेंट्री के बफर स्टॉक तैयार करें और संयंत्रों में कर्मचारी की आवाजाही की व्यवस्था करें। आईटीसी के प्रवक्ता ने कहा, 'हमने सैवलॉन स्वच्छता उत्पादों और आशीर्वाद आटा जैसे आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण जारी रखने के लिए अधिसूचित स्थानों के अधिकारियों से मंजूरी मांगी है।'

अप्रैल से पहले एचडीएफसी के नए सीईओ के नाम की घोषणा

सुब्रत पांडा
मुंबई, 23 मार्च

निजी क्षेत्र के बैंक, एचडीएफसी बैंक अप्रैल से पहले नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नाम की घोषणा करेगा जो मौजूदा सीईओ आदित्य पुरी की जगह लेंगे। पुरी का कार्यकाल अक्टूबर 2020 में खत्म हो रहा है जो दशकों से इस बैंक का नेतृत्व कर रहे थे।

आदित्य पुरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चयन समिति को कई नाम की सिफारिशें मिली हैं और अप्रैल से पहले उस व्यक्ति के नाम की घोषणा कर दी जाएगी जो बैंक को भविष्य में आगे ले जाएंगे।

करीब ढाई साल पहले बैंक ने दूरसंचार, कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आदि में प्रगति देखते हुए अपने कारोबारी में मॉडल में बदलाव करने का फैसला किया था। बैंक ने इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए एक नियुक्ति भी की थी जिसने पुरी के प्रतिनिधि के तौर पर पूरे बदलाव को अंजाम दिया।

बैंक में भी इस भूमिका के लिए कई बेहतर उम्मीदवार हैं लेकिन अब बैंक ने शीर्ष नेतृत्व के लिए किसी बाहरी उम्मीदवार को लाने का फैसला किया है। इस बाबत अब सबकुछ हो चुका है और चयन समिति के पास सिफारिशें भी जा चुकी हैं।

पुरी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक को रीपो दर में कटौती और परिसंपत्ति गुणवत्ता जैसे नियमों में थोड़ी ढील देने जैसे कदम तत्काल प्रभाव से उठाए जाने की जरूरत है ताकि कोरोनावायरस महामारी से बड़ी संकटपूर्ण स्थिति और बंदी के झटके सहने के लिए तैयार रहा जा सके। उनका कहना था कि आरबीआई के पास परिसंपत्ति वर्गीकरण नियमों में कुछ छूट देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनके बैंक में चौथी तिमाही में वृद्धि में मंदी दिख सकती है लेकिन बैंक के पास 5 अरब डॉलर की अतिरिक्त नकदी है। इससे उन्हें मुश्किल वक्त से उबरने में मदद मिलेगी। एचडीएफसी बैंक ने भी खुदरा ऋण लेने के नियमों को सख्त बनाया है। हालांकि उन्होंने आपात स्थिति के लिए ग्राहकों के लिए किसी ऋण योजना की बात खारिज करते हुए कहा कि वे मुश्किल समय में योग्य कर्जदारों को ही मदद करेंगे।

पुरी ने कहा, 'भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सरकार से पूंजी पाता है लेकिन हमें बाजार से पूंजी उगाही करनी होती है। ऐसे में हम कोई ऐसा कारोबार नहीं कर सकते हैं जो मुनाफादायक न हो।'

एक्सचेंजों की आपदा रिकवरी साइट सक्रिय

स्टॉक एक्सचेंजों ने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुए भारी गतिरोध को देखते हुए अपनी आपदा रिकवरी साइटों को सक्रिय कर दिया है। यह कदम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से बाजार ढांचागत संस्थानों (एमआईआई) के लिए कारोबारी निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा रिकवरी के बारे में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप उठाया गया है। बाजार ढांचागत संस्थानों की श्रेणी में स्टॉक एक्सचेंजों के अलावा क्लियरिंग निगम एवं डिपॉजिटरी भी शामिल हैं। इसका कदम का मकसद यह है कि किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एक्सचेंज उससे निपटने के लिए तैयार रहें जिससे कोई भी गतिरोध बाजार की निष्ठा एवं निवेशकों के भरोसे पर चोट न पहुंचा सके।

सेबी से जुड़े एक सूत्र ने सोमवार को बताया कि स्टॉक एक्सचेंजों ने परिचालन को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए समुचित व्यवस्था लागू की है। *बीएस*

आईटी कंपनियों के मुद्रा लाभ को कारोबार में उथल-पुथल का झटका

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक लुढ़क चुका है, लेकिन कोरोनवायरस (कोविड-19) के प्रकोप के कारण भारतीय भारतीय सॉटवेयर सेवा प्रदाताओं की यह खुशी गायब हो गई है।

आईटी क्षेत्र पर नजर रखने वाले विश्लेषकों ने कहा कि कोविड-19 से न केवल आईटी सेवा कंपनियों का प्रमुख कारोबार प्रभावित होने की आशंका है, बल्कि इससे नए सौदे हासिल होने में भी देरी होगी। इंडियानिवेश के वरिष्ठ विश्लेषक हरित शाह ने कहा, 'मुद्रा में गिरावट के बावजूद तमाम कारक चिंताजनक हैं। कोविड-19 के कारण उनके कामकाज के प्रवाह और मांग में अनिश्चितता दिख रही है।' सेंट्रम ब्रोकिंग के विश्लेषक मधु बाबू ने कहा कि आईटी कंपनियों के प्रमुख कारोबार में गिरावट से इन कंपनियों के डॉलर राजस्व में कमी आने की आशंका है। इससे रुपये में गिरावट से होने वाले फायदे का कोई मतलब नहीं होगा। *बीएस*

श्रमिकों को मिले...

पृष्ठ 1 का शेष

फिक्की ने यह भी मांग की है कि कोरोनावयरस से प्रभावित कंपनियों के नए मामले ऋण शोधन एवं दिवालिया संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में नहीं लाए जाने चाहिए। फिक्की एवं सीआईआई दोनों प्रमुख औद्योगिक संगठनों ने कहा है कि उन्होंने जितनी भी मांगें रखी हैं, उनसे सरकार की वित्तीय स्थिति पर कोई खास असर नहीं होगा। कर्मचारियों का वेतन नहीं काटने की प्रधानमंत्री की सलाह पर उद्योगपतियों ने कहा कि उन्होंने आवश्वस्त किया है कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी और उनके वित्तीय हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उद्योग जगत ने इस खतरनाक वायरस के साथ लड़ाई में सरकार को सभी तरह का सहयोग देने की भी बात कही है। फिक्की कोरोनावायरस के संदिग्धों एवं मरीजों को एकांतवास में रखने के लिए बेड एवं जीवन रक्षक उपकरण मुहैया कराने पर नीति आयोग के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी तरह, सीआईआई आपात स्वास्थ्य जरूरतों के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं उपकरण के उत्पादन एवं इनकी उपलब्धता के लिए अपने संयंत्रों का इस्तेमाल करने देगा।

आधे शेयर मई 2014 से नीचे

बीएसई-500 के 408 में 188 शेयरों ने पिछले छह साल की अपनी बढ़त गंवा दी है और शेयरधारकों को करीब 20 लाख करोड़ रुपये का झटका दिया है

कृष्ण कांत
मुंबई, 23 मार्च

कोरोनावायरस के कारण इक्विटी बाजार में मचे हाहाकार ने लंबी अवधि के निवेशकों को परेशान करना शुरू कर दिया है जो पांच साल या ज्यादा अवधि के लिए शेयर खरीदते और उसमें निवेशित रहते हैं। बीएसई-500 इंडेक्स में शामिल करीब आधे शेयर अब मई 2014 के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे।

बाजार में तेज गिरावट के बाद बीएसई-500 के 408 में से 188 शेयरों ने नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार की तरफ से 25 मई 2014 के सत्ता संभालने के बाद से हुई पूरी बढ़ोतरी गंवा दी है। ये 188 शेयर अब 25 मई 2014 के स्तर से नीचे कारोबार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी।

आज कारोबार के दौरान बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स 13.15 फीसदी नीचे जबकि एनएसई निफ्टी 13 फीसदी गिरकर बंद हुआ। बीएसई 500 इंडेक्स में भी 13 फीसदी की गिरावट आई और यह 1463 अंक टूटा।

मनमोहन सिंह के कार्यकाल के स्तर पर कारोबार कर रहे कुछ शेयरों में एलऐंडटी, इंडसइंड बैंक, ऐक्सिस बैंक, आईटीसी, एमऐंडएम, अपोलो टायर्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनैंस, टाटा मोटर्स, एमऐंडएम फाइनैंशियल सर्विसेज, वेदांत, मदरसन सूमी, बॉश, एलऐंडटी फाइनैंस होल्डिंग्स, आईडीएफसी, केनरा बैंक, प्रेस्टीज एस्टेट्स, एडलवाइस फाइनैंस, ल्यूपिन, सिप्ला और सन फार्मा शामिल हैं।

विश्लेषक इसके लिए आर्थिक मंदी और कोरोना के कारण हुई बंदी से आर्थिक अवरोध के चलते कंपनियों की आय में तेज गिरावट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इक्विनॉमिक्स रिसर्च ऐंड एडवाइजरी के संस्थापक व प्रबंध निदेशक जी चोकालिंगम ने कहा, आर्थिक गतिविधियों में तेज गिरावट की आशंका है और कंपनियों की आय भी अल्पावधि में घटने की संभावना है, जिसकी वजह कोरोनावायरस का प्रसार है।

25 मई 2014 के बाद से इन 188 शेयरों में प्रवर्तकों समेत शेयरधारकों ने लगभग 19.4 लाख करोड़ रुपये गंवाए हैं। ये शेयर समीक्षाधीन अवधि के दौरान औसत तौर पर 45 प्रतिशत नीचे हैं।हालांकि शेयर कीमतों और बाजार पूंजीकरण में ज्यादा गिरावट 20 फरवरी 2020 से देखी गई है, जब बाजार में कोरोनावायरस महामारी से आर्थिक मंदी गहराने की आशंका पैदा हुई। गहन आकलन से संकेत मिलता है कि गिरावट के शिकार हुए इन 188 शेयरों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में लगभग 82 प्रतिशत की कमजोरी 20 फरवरी से आई है।

बिजनेस स्टैंडर्ड के सैम्पल में शामिल किए गए बीएसई-500 सूचकांक के 400 शेयरों के सभी शेयरधारकों ने 20 फरवरी से अब तक 47.2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाया।कोरोनावायरस से संबंधित बिकवाली का बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस के बाजार पूंजीकरण में फरवरी 2020 से लगभग 70 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिसके बाद इंडसइंड बैंक (71.5 प्रतिशत) और वेलस्पन कॉर्प (66.4 प्रतिशत की गिरावट) शामिल रहे हैं।

पिछले एक महीने में बड़ी गिरावट दर्ज करने वाले अन्य शेयरों में श्रीराम ट्रांसपोर्ट (-66.3 प्रतिशत), पीरामल एंटरप्राइजेज (-66 प्रतिशत), एमऐंडएम फाइनैंशियल सर्विसेज (-60.8 प्रतिशत), ऐक्सिस बैंक (-58.6 प्रतिशत), अशोक लीलैंड (-57.3 प्रतिशत), मदरसन सूमी (-56.6 प्रतिशत) और यूपीएल (-56.1 प्रतिशत) शामिल रहे।

बाजार को फंसे कर्ज और उधारी क्षेत्र में चूक के मामले बढ़ने की आशंका है, क्योंकि वायरस को नियंत्रित करने के उपायों से आर्थिक गतिविधि में बड़ी गिरावट का जोखिम गहरा गया है और कंपनियों तथा परिवारों की आय एवं नकदी प्रवाह पर नकारात्मक असर देखा जा सकता है।

छह साल में शीर्ष 10 कंपनियों का घाटा

शेयर का बंद भाव

कंपनी	वर्तमान बाजार कैप (करोड़ रुपये)	23 मई 2014 (कीमत रु.)	23 मार्च 2020 (कीमत रु.)	बदलाव (प्रतिशत)
आईटीसी	189792.1	228.1	154.4	-32.3
एसबीआई	162070.9	275.53	181.6	-34.1
एलऐंडटी	101588.9	1007.74	723.7	-28.2
विप्रो	97326.3	183.38	170.35	-7.1
ऐक्सिस	86999.1	372.99	308.35	-17.3
कोल इंडिया	78698.0	397.55	127.7	-67.9
सन फार्मा	77738.5	584.7	324	-44.6
इंडियन ऑयल	76113.5	90.76	80.85	-10.9
ओएनजीसी	76047.8	271.67	60.45	-77.7
एनटीपीसी	75396.5	133.62	76.2	-43.0

स्रोत- कैपिटालाइन, संकलन- बीएस रिसर्च

चूक के बढ़ते भय से कॉरपोरेट बॉन्ड का प्रतिफल चढ़ा

अनूप रॉय
मुंबई, 23 मार्च

कॉरपोरेट बॉन्ड का प्रतिफल बढ़ा है और इस तरह से सरकारी बॉन्ड और उनके बीच स्प्रेड बढ़ गया है क्योंकि कोरोनावायरस के कारण आई मंदी के कारण कंपनियों की तरफ से डिफॉल्ट की आशंका से निवेशक उनसे दूर हट रहे हैं।

इंडसइंड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री गौरव कपूर ने कहा, स्थानीय बॉन्ड बाजार पहले से ही एनबीएफसी संकट के कारण काफी समझदार हो गया है, ऐसे में सरकार समर्थित पीएसयू या मजबूत क्रेडिट वाली कंपनियों के इश्यू का वर्चस्व है। रोलिंग ओवर और पुनर्वित्त निश्चित तौर पर मुश्किल हो गया है, खास तौर से इसलिए क्योंकि स्प्रेड बढ़ा है।

समान परिपक्वता वाले सरकारी व कॉरपोरेट बॉन्डों के बीच स्प्रेड भी इस अवधि में खासा बढ़ा है। एएए और एए बॉन्ड का स्प्रेड 3 मार्च को क्रमश: 95 आधार अंक और 166 आधार अंक था। अब यह बढ़कर क्रमश: 130 आधार अंक और 197 आधार अंक पर पहुंच गया है।

एनबीएफसी प्रतिभूतियों का प्रतिफल भी बढ़कर अब 8.5 फीसदी हो गया है, जो 3 मार्च को 7.25 फीसदी था। इस तरह से कहा जा सकता है कि एनबीएफसी का प्रतिफल अब अक्टूबर 2018 के स्तर पर पहुंच गया है। कोटक म्युचुअल फंड ने एक रिपोर्ट में ये बातें कही है।

म्युचुअल फंड ने कहा है, प्रभावी तौर पर बाजार ने पिछली सभी ब्याज कटौती, नीतिगत कदम और खरीदारी समर्थन को भूलने का फैसला किया है। तीन साल का बैंकों का एमसीएलआर 7.85-8 फीसदी के दायरे में है, तीन साल का एचडीएफसी 8.25 फीसदी पर ट्रेड कर रहा है, तीन साल का बजाज फाइनैंस करीब 8.5 फीसदी पर। तीन साल का आरईसी 8 फीसदी पर कारोबार कर रहा है। ये एनबीएफसी-एचएफसी अल्पावधि से मध्यम अवधि में शायद ही पूंजी बाजार से उधार लेना पसंद करेंगे।

उपभोक्ता मांग पर झटके की संभावना से कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक व सरकार से विशेष छूट की मांग कर रही हैं। बजाज समूह के वित्त निदेशक प्रबाल बनर्जी ने कहा, बॉन्ड और कर्ज भुगतान में चूक काफी ज्यादा बढ़ेगी, अगर आरबीआई मूलधन भुगतान पर दो साल की मोहलत और ब्याज भुगतान पर छह महीने से एक साल की मोहलत नहीं देता। बैंक के एनपीए पर इस मंदी का गहरा असर होगा। ऐसी ही बातें एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ आदित्य पुरी ने भी कही। रेटिंग एजेंसी के अधिकारी भी डिफॉल्ट को लेकर चिंतित हैं।

राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो 36 फीसदी गिरा

आशिष कचोलिया और डॉली खन्ना को भी लगा झटका

दीपक कोरगांवकर और पुनीत वाधवा
मुंबई/नई दिल्ली, 23 मार्च

कोरोनावायरस महामारी के कारण शेयर बाजार में मचे हाहाकार से मुख्य सूचकांकों एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी-50 में इस कैलेंडर वर्ष में अब तक 37 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के करीब 54 लाख करोड़ रुपये बाजार पूंजीकरण स्वाहा हो गए हैं।

इस हाहाकार के बीच धनाढ्य निवेशकों मसलन राकेश झुनझुनवाला ऐंड फैमिली, आशिष धवन, अनिल कुमार गोयल ऐंड फैमिली, आशिष रामचंद्र कचोलिया और डॉली खन्ना की हैसियत पर भी भारी चोट पड़ी है। भारतीय इक्विटी बाजार के बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला ऐंड फैमिली ने वित्त वर्ष 2020 में अब तक 4,558 करोड़ रुपये गंवाए हैं और उनके निवेश की कीमत 10,000 करोड़ रुपये से नीचे आ गई है। सोमवार के बंद भाव के आधार पर सूचीबद्ध कंपनियों में राकेश झुनझुनवाला ऐंड फैमिली का कुल निवेश 8,021 करोड़ रुपये रह गया है, जो दिसंबर 2019 के आखिर के 12,480 करोड़ रुपये के मुकाबले 36 फीसदी कम है।

जहां उनका निवेश एक फीसदी से ज्यादा है उसके बारे में ताजा शेयरधारिता पैटर्न के आंकड़ों से पता चलता है कि इन निवेशकों को मिडकैप व स्मॉलकैप कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट से भारी झटका लगा है क्योंकि इस अवधि में

राकेश झुनझुनवाला

मिडकैप व स्मॉलकैप सूचकांक में 35 फीसदी की गिरावट आई है।

टाइटन का शेयर 33 फीसदी टूटकर 52 हफ्ते के निचले स्तर 775 रुपये प्रति शेयर रह गया है, जहां पत्नी रेखा झुनझुनवाला के साथ राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 6.09 फीसदी है और कैलेंडर वर्ष 2020 में इसकी कीमत में 2,314 करोड़ रुपये की चोट पड़ी है। टाइटन में झुनझुनवाला का निवेश दिसंबर 2019 की तिमाही के शेयरधारिता पैटर्न के आधार पर अब 4,710 करोड़ रुपये बैठता है। एनसीसी, डेल्टा कॉर्प, करूर वैश्य बैंक, एप्टेक और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल हैं और उनमें भी काफी झटका लगा है और इस अवधि में ये 50 फीसदी से ज्यादा टूटे हैं।

फीसदी के लिहाज से अनिल कुमार गोयल और सीमा गोयल के पोर्टफोलियो में औसत कमी 54 फीसदी यानी 405 करोड़ रुपये की रही है, जिनके पोर्टफोलियो में धामपुर शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग ऐंड इंडस्ट्रीज, द्वारिकेश शुगर और उत्तम शुगर्स शामिल हैं। दूसरी ओर अन्य निवेशकों मसलन आशिष धवन, आशिष रामचंद्र कचौलिया और डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो पर इस साल अब तक 44 फीसदी से 50 फीसदी तक की चोट पड़ी है।

हालांकि इस पर कोई राय नहीं है कि कोरोना का असर बाजार पर कब तक रहेगा, लेकिन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने कहा कि वास्तविक असर मंदी के कारण मांग पक्ष से देखने को मिलेगा। इससे कीमतें धीरे-धीरे घटेंगी और अंतत: ज्यादातर कंपनियों की रफ्तार प्रभावित होगी।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के चिराग शाह और धवन शाह ने एक नोट में कहा है, अगली दो तिमाहियों में कोविड-19 के ज्यादातर नकारात्मक नतीजों को दुनिया भर के सूचकांकों ने समाहित कर लिया है। हालांकि इससे भी ज्यादा देर होती है या संक्रमण बढ़ता है तो और नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में इक्विटी सूचकांकों में और गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बीच, मिडकैप व स्मॉलकैप क्षेत्रों का मूल्यांकन लंबी अवधि के औसत से नीचे चला गया है।

झुनझुनवाला के निवेश पर असर

कंपनी	हिस्सेदारी फीसदी	शेयर की कीमत रुपये में 31 दिसंबर 2019	23 मार्च 2019	गिरावट (फीसदी)
डेल्टा कॉर्प	7.39	197.95	59.75	-69.8
एनसीसी	10.38	56.00	18.75	-66.5
वीआईपी इंडस्ट्रीज	5.11	432.15	208.75	-51.7
जियोजित फाइनैंशियल	7.57	28.00	15.95	-43.0
एग्रो टेक फूड्स	7.41	626.00	368.30	-41.2
क्रिसिल	5.48	1910.25	1160.40	-39.3
टाइटन कंपनी	6.69	1187.60	798.05	-32.8

राकेश झुनझुनवाला ऐंड फैमिली के शेयरों का प्रदर्शन, दिसंबर 2019 की तिमाही में 5 फीसदी से ज्यादा शेयरधारिता, स्रोत : कैपिटालाइनप्लस/बीएसई

कोरोनोवायरस के कारण वैश्विक कॉरपोरेट राजस्व को लगेगा झटका

12 लाख करोड़ डॉलर का हो सकता है नुकसान

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 23 मार्च

कोरोनोवायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी की वजह से अमेरिकी कंपनियों को 4 लाख करोड़ डॉलर का झटका लगने की आशंका है। अमेरिकी हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स की एक ताजा रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स लगभग 350 संस्थागत ग्राहकों के 160 अरब डॉलर के वैश्विक निवेश का प्रबंधन करता है। ब्रिजवाटर के अनुसार इसका वैश्विक प्रभाव कहीं अधिक है।

ब्रिजवाटर के सह-मुख्य निवेश अधिकारी ग्रेग जेन्सन ने एक रिपोर्ट में लिखा है, 'अभी हमें लगता है कि अमेरिका में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के राजस्व में लगभग 4 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट आएगी। यह एक बहुत ही खतरनाक गिरावट है। यदि इसे कम नहीं किया गया तो इसका दूरगामी प्रभाव दिखेगा। चूंकि दुनिया भर में कॉरपोरेट राजस्व को इस प्रकार का झटका लगने जा रहा है, इसलिए कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर यह करीब तिगुना यानी करीब 12 लाख करोड़ डॉलर के नुकसान की आशंका है।'

इस लिहाज से अमेरिकी कंपनियों की पूंजीगत खर्च योजना में 900 अरब डॉलर (सकल घरेलू उत्पाद का 4 फीसदी) की कटौती होने और पुनर्खरीद एवं विलय-अधिग्रहण मद में करीब 600 अरब डॉलर

(जीडीपी का 3 फीसदी) की कटौती होने की आशंका है। रोजगार में भी उल्लेखनीय कटौती होगी क्योंकि कंपनियां नियुक्तियों में कमी करेगी जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ब्रिजवाटर का कहना है कि ये अनुमान तीन उपायों की गणना के आधार पर जाहिर किए गए हैं। पहला, एक साधारण रियायती नकदी प्रवाह मॉडल के उपयोग से शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण राजस्व नुकसान को नियंत्रित करता है। दूसरे के तहत अनुमानों में वृद्धि का उपयोग किया जाता है (जहां कंपनियों या विश्लेषकों ने उन्हें बताया है) और बाजार मूल्य निर्धारण का उपयोग करते हुए उसे आगे बढ़ाया जाता है। तीसरे के तहत माना गया है कि अमेरिका में उन क्षेत्रों के राजस्व को झटका लगेगा जिससे संबंधित क्षेत्रों को चीन में पहले ही झटका लग गया है। ब्रिजवाटर की रिपोर्ट में कहा गया है, 'बिना किसी उल्लेखनीय राजकोषीय अथवा मौद्रिक हस्तक्षेप के 4 लाख करोड़ डॉलर का मतलब अमेरिका के जीडीपी में इस साल 6 फीसदी से अधिक की गिरावट होगी। हमें दूसरी तिमाही में सबसे अधिक गिरावट दिखेगी और उस दौरान गतिविधियों में 2019 के अंत के स्तर के मुकाबले 10 फीसदी से अधिक की कमी दिखेगी।'

जेन्सन का कहना है कि दूसरी तिमाही में अमेरिकी कंपनियों की वार्षिक वृद्धि में 30 फीसदी से अधिक की गिरावट दिख सकती है। परिणामस्वरूप बहीखाते से अधिकतर कॉरपोरेट मुनाफे और नकदी का सफाया हो जाएगा। ब्रिजवाटर ने अपने सुझाव में कहा है, 'जब क्षेत्र और कंपनी स्तर पर जाकर राजस्व में गिरावट को नकदी प्रवाह अंतर का आकलन करते हैं तो हमें ऊर्जा, यात्रा एवं पर्यटन में लगभग 2 लाख करोड़ की कमी दिखती है। साथ ही यह बड़ी और छोटी कंपनियों के बीच समान रूप से विभाजित दिखता है। कई कंपनियां ऋण के जरिये इस अंतर को पाटने की कोशिश करेंगी जिससे उनका ऋण बोझ बढ़ेगा।'

वित्तीय उद्योग की बढ़ेगी चिंता

जेन्सेन का मानना है कि इन परिस्थितियों में कंपनियां दिवालिया होने लगेंगी। उनके आकलन के अनुसार, बाजार को करीब 850 अरब डॉलर का नुकसान होगा जिसमें से करीब एक तिहाई का झटका केवल बैंकों को लगेगा। उन्होंने कहा, 'भले ही इससे वित्तीय प्रणाली अथवा बैंकों की स्थिति कमजोर न हो क्योंकि उनके पास काफी पूंजी और नकदी प्रवाह होती है लेकिन यह सख्ती बरतने के लिए वित्तीय क्षेत्र पर काफी दबाव डालेगा।' जेन्सन का मानना है कि इस झटके से निपटने के लिए विभिन्न सरकारों की क्षमता अलग-अलग होती है और आगे चलकर बाजार इससे काफी हद तक संचालित होगा। इस लिहाज से अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इस मामले में काफी सक्रियता दिखाते हुए अल्पकालिक कॉरपोरेट ऋण खरीद को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। हाल में उसने अल्पकालिक दरों में 0 फीसदी से 0.25 फीसदी के दायरे में कटौती की है।

जहां तक भारत का सवाल है तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी बाजार की चिंताओं को दूर करने के लिए उपाय किए हैं। उसमें कहा गया है कि भारत सरकार से आर्थिक प्रोत्साहन के लिए मांग बढ़ रही है। विश्लेषकों का कहना है कि कमजोर राजकोषीय स्थिति के कारण सरकार अभी अधिक आक्रमकता नहीं दिखा रही है।

जेफरीज के महेश नंदुरकर ने एक हालिया रिपोर्ट में लिखा है, 'हमें लगता है कि सरकार जल्द ही आर्थिक सहायता के लिए उपाय करेगी लेकिन कर संग्रह में कमी आने से राजकोषीय स्थिति सीमित हो सकती है। यदि सरकार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 1 फीसदी कम करने का निर्णय लेती है इससे 18 अरब डॉलर के खर्च की गुंजाइश होगी।'

सीएसआर की राशि कोरोना पर खर्च हो सकेगी

सरकार ने कंपनियों को दी इजाजत, 31 मार्च तक सीएसआर का धन खर्च करने के लिहाज से यह अहम फैसला

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 23 मार्च

वैश्विक आपदा कोरोना में कंपनियों के अंशदान को अनुमति देने के मकसद से आज सरकार ने इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी (सीएसआर) गतिविधि में शामिल कर दिया है।

वैश्विक महामारी
कोरोनावायरस

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, 'भारत में कोरोनावायरस के प्रसार को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने इसे वैश्विक आपदा घोषित किया है और भारत सरकार ने इसे आपदा के रूप में अधिसूचित किया है। ऐसे में कोविड-19 के लिए सीएसआर फंड को खर्च किया जा सकता है और यह सीएसआर गतिविधि में है।'

कंपनियां अपने सीएसआर फंड को अनुसूची 7 में सूचीबद्ध कार्यों स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार, निवारक स्वास्थ्य सेवा, साफ सफाई और आपदा प्रबंधन के तहत खर्च कर सकती हैं। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है, 'अनुसूची 7 में शामिल कार्यों का दायरा व्यापक है और इस उद्देश्य के लिए इसकी व्याख्या उदार तरीके से की जा सकती है।' अनुसूची 7 में प्रधानमंत्री राहत कोष, स्वच्छ भारत कोष जैसे कई कोष शामिल किए गए हैं।

पिछले सप्ताह सरकार ने पंजीकृत निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 के जांच की अनुमति दे दी थी।

कॉर्पोरेट क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम तिथि मार्च के निकट आने के साथ इसके आवंटन का उचित विकल्प देखा जा रहा है। हाल की अधिसूचना से उम्मीद है कि इस आपदा में अंशदान में मदद मिल सकेगी।

पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनर अंशुल जैन ने कहा, 'कई कंपनियां हैं, जो सरकार को अंशदान देकर समर्थन करना चाहती थीं, लेकिन यह साफ नहीं था कि वे निवारक स्वास्थ्य देखभाल या आपदा प्रबंधन के तहत इसे खर्च कर सकती हैं या नहीं। एमसीए की इस अधिसूचना से भ्रम दूर करने में मदद मिलेगी।'

सरकार ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के लिए मसौदा नियम पेश किया है, जिसमें सीएसआर के सख्त मानक हैं और कंपनियों को सीएसआर गतिविधियों का व्यापक ब्योरा देना होगा और इस बात की निगरानी बढ़ाई जाएगी कि किस तरह से ऐसे धन का इस्तेमाल किया गया है।

कंपनियों को अब व्यापक ब्योरा पेश करना होगा। यह सिर्फ न केवल चल रही परियोजनाओं के लिए होगा बल्कि अन्य परियोजनाओं पर भी यह लागू होगा। रिपोर्टिंग सिर्फ चालू वित्त वर्ष तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसे पहले के वित्त वर्षों तक भी बढ़ाया जाएगा।

इस मकसद के लिए सरकार ने चल रही परियोजनाओं की परिभाषा भी तय की है। इसके मुताबिक कंपनी की ओर से कई साल तक के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं में सीएसआर बाध्यताओं का पालन करना होगा और जिस वित्त वर्ष में परियोजना शुरू की गई है, उसे छोड़कर इसकी समयसीमा 3 साल से ज्यादा नहीं होगी।

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक कंपनियों को अलग प्रारूप में सीएसआर की खर्च की गई राशि या बची राशि का ब्योरा आगामी तीन वर्षों के लिए देना होगा। आर्थिक गतिविधियों पर वैश्विक महामारी का असर व्यापक तौर पर महसूस किया जा रहा है और विमानन, यात्रा, पर्यटन व आतिथ्य सत्कार क्षेत्रों पर इसका असर ज्यादा है।

सोमवार को कोझीकोड में केएसआरटीसी बस स्टैंड के परिसर में कीटाणुनाशक का छिड़काव करते कर्मचारी -पीटीआई

सीएसआर कोष पर स्थिति साफ

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना को आपदा घोषित किए जाने के बाद अब सीएसआर कोष का धन इसमें इस्तेमाल हो सकता है
- जानकारों का कहना है कि 31 मार्च तक सीएसआर का बजट खर्च करना है, जिसे देखते हुए उचित विकल्प देखा जा रहा था
- सरकार ने कहा है कि अनुसूची 7 का दायरा व्यापक, इसकी उदार व्याख्या की जा सकती है

आयुष्मान भारत लागू करेगी दिल्ली सरकार

बीएस संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 23 मार्च

दिल्ली विधानसभा ने सोमवार को वित्त वर्ष 2020-21 का 65,000 करोड़ रुपये का बजट पारित कर दिया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानभा में बजट पेश किया। इसमें कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

लगातार छठी बार बजट पेश करते हुए सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लागू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष 2020-21 से राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करेगी। यह घोषणा सरकार के पूर्व रुख के उलट है।

उन्होंने कहा, 'दिल्ली सरकार 2020-21 से आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करेगी। इसमें हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। यह योजना दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भारती जनता पार्टी के बीच विवाद का विषय रहा है।

सरकार ने दिल्ली में डीटीसी की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा अगले वित्त वर्ष में भी जारी रखने की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल सरकार पर योजना के रास्ते में रोड़ा अटकाने और दिल्ली की जनता को उसके लाभों से वंचित करने का आरोप लगाती रही थी। आम आदमी पार्टी के पिछले महीने विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद सत्ता में आने के पश्चात यह पहला बजट है। वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय पिछले पांच साल में 44 प्रतिशत बढ़ी है। बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। इस बारे में उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल के विकास मॉडल में ये दोनों क्षेत्र सबसे ऊपर है।

बीएस बातचीत

जीडीपी अनुमान पर करेंगे विचार, अभी वक्त

मुख्य आर्थिक सलाहकार **कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन** ने **अरूप रॉयचौधरी** से कहा कि कोविड-19 के कारण देश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी, जो कम से कम 31 मार्च तक चलेगा। प्रमुख अंश..

यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना गंभीर मामला है? क्या प्रभाव के हिसाब से इसकी तुलना 2008 की वैश्विक आर्थिक से की जा सकती है?

अगर भारत के हिसाब से देखें तो आपको आंकड़े देखते समय आज की तुलना में कल को लेकर भी सावधान रहना होगा। लेकिन आज के आंकड़ों के मुताबिक अगर आप अन्य सभी देशों की स्थिति को देखें और सांख्यिकीय मॉडलों का पालन करें तो अभी रास्ता है। पहला स्टेज-1 है, उसके बाद स्टेज-2 होता है। हम इस समय स्टेज-2 में हैं। और मुझे लगता है कि यह अच्छी खबर है कि इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक हमारे यहां कम्युनिटी में प्रसार नहीं हो रहा है। सामुदायिक प्रसार से यह बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए इस हिसाब से देखें रैखिक वृद्धि हो रही है और सामुदायिक प्रसार नहीं है। मैं भविष्य के बारे में कुछ कहने को लेकर सावधानी बरतूंगा। लेकिन आज के हिसाब से देखें तो आंकड़ों से लगता है कि हम अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

स्वास्थ्य समस्या के साथ ही इसका आर्थिक असर भी होगा। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं आपको उतार चढ़ाव को बराबर करने की जरूरत है। आव स्वास्थ्य संसाधनों और लोगों की संख्या में तालमेल बिठाकर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस खाई को पाटने के लिए लॉकडाउन जैसे कदम उठाने की जरूरत होगी। इसका भी आर्थिक असर होगा। इस तरह से देखें तो साफतौर पर दोनों में संबंध है।

ऐसे में मेरे विचार से वैश्विक वित्तीय संकट और वैश्विक महामारी में अंतर है। वैश्विक वित्तीय संकट केवल वित्तीय क्षेत्र की समस्या थी। और जब संकट वित्तीय क्षेत्र से बाहर निकलता है तो यह लंबा खिंच जाता है।

क्या यह वक्त है कि 2019-20 और 2020-21 के जीडीपी अनुमान पर फिर से विचार किया जाए?

यह वक्त अनिश्चितता का है, जिसमें सब कुछ अज्ञात है। आप एक दिशा में विचार कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी आंकड़े में अहम त्रुटि की संभावना है। इस तरह की अनिश्चितता में मात्रात्मक अनुमान दरअसल बहुत कठिन है। इस पर हम आंतरिक आकलन कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें त्रुटि की बहुत संभावना है। अप्रैल और मई भी प्रभावित हो सकता है। बहरहाल अभी नए आंकड़ों के बारे में अनुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि स्थिति लगातार बदल रही है।

क्या इसका असर कर राजस्व व विनिवेश से होने वाली आमदनी पर पड़ेगा?

इसका असर होगा। फिर भी अच्छी बात यह है कि लक्ष्य पूरे साल का है। इन मसलों पर पहले ही काम किया जा चुका है। मुझे लगता है कि समय भी प्रभावित हो सकता है। इन सभी विषयों पर हम विचार करेंगे। मुझे लगता है कि इस समय अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन मुझे लगता है कि यह साल भर के लिए किया जाना चाहिए।

आर्थिक हिसाब से सरकार आगे क्या करने जा रही है?

व्यापक रूप से देखें तो मुझे लगता है कि केंद्र, रिजर्व बैंक और वित्तीय क्षेत्र को तालमेल की जरूरत है। व्यापक तस्वीर को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाने चाहिए और साथ ही उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखना होगा, जो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

ग्राहकों को पहले पेंशन देगा ईपीएफओ

सोमेश झा
नई दिल्ली, 23 मार्च

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने 65 लाख खाताधारकों को इस मार्च के समाप्त होने के पहले मासिक पेंशन जारी कर देगा, जिससे कि कोविड-19 कोरोनावायरस के कारण फंसे ग्राहकों को मदद मिल सके।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से आज जारी एक बयान के मुताबिक, 'वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के कारण देश के तमाम हिस्सों में लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस असाधारण स्थिति में पेंशनभोगियों को कोई असुविधा न होने पाए, इसे देखते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अपने फील्ड ऑफिसरों को निर्देश दिया है कि वे पेंशनभोगियों का लेखा जोखा और चालू महीने की राशि के बारे में ब्योरा 25 मार्च 2020 तक तैयार करें।'

इसमें कहा गया है कि ईपीएफओ के सीपीएफसी सुनील बर्थवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसे बैंकों को भेजा जाए, जिससे पेंशनभोगियों के खाते में राशि उनके खाते में मार्च महीने में ही डाली जा सके।

एक अधिकारी ने बताया कि ईपीएफओ सामान्यतया पेंशन जारी करने का ब्योरा बैंकों को माह के आखिरी कार्यदिवस को भेजता है (इस मामले में यह 31 मार्च होगी)। ग्राहक के खाते में अगले महीने के पहले सप्ताह में पेंशन आ जाती है। अब यह समयसीमा पहले कर दी गई है।

इस माह की शुरुआत में ईपीएफओ ने एक बयान जारी कर अपने ग्राहकों से कहा था कि वह विभिन्न ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाएं, जिसमें उनके भविष्य निधि के दावे भी शामिल हैं। कोविड-19 वायरस के कारण सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है। तमाम निजी कार्यालयों को या तो बंद कर दिया गया है या कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है।

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ 3 योजनाएं चलाता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना। कर्मचारी अपने वेतन का 12 प्रतिशत (मूल वेतन और महंगाई भत्ते का) इस योजना में देते हैं और इतनी ही राशि नियोक्ता को देना होता है। इसमें से कर्मचारियों का 8.33 प्रतिशत अंशदान ईपीएस में जाता है और सरकार इसमें वेतन का 1.16 प्रतिशत अंशदान कर्मचारियों के पेंशन खाते में करती है। इस समय 15,000 रुपये महीने पाने वाले कर्मचारियों के वेतन का 8.33 प्रतिशत उनके ईपीएस खाते में जाता है। जिन कर्मचारियों का वेतन 1 सितंबर 2014 के बाद 15,000 रुपये प्रति माह से ज्यादा है, उनका पेंशन खाता नहीं है। ईपीएस फंड ईपीएफओ के साथ जुड़ा हुआ खाता है, जिसके तहत खाताधारकों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है, अगर उन्होंने 10 साल नौकरी की हो।

ईपीएस के तहत कर्मचारी को 58 साल उम्र के बाद से मृत्यु होने तक पेंशन मिलती है। पेंशन की राशि पेंशन वाले वेतन, मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर पिछले 60 महीनों की कर्मचारी की सेवा के वेतन के औसत के आधार पर तय होती है।

2014 में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने सभी ग्राहकों को न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये देने की घोषणा की थी, जो योजना सितंबर 2014 से लागू है। इस कदम से हर साल 18 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होता है।

कोरोना संकट में मदद

- ईपीएफओ करेगा पेंशनधारकों को मार्च के अंत तक पेंशन का भुगतान
- कोविड में फंसे ग्राहकों की मदद
- ईपीएफओ ने ग्राहकों से तमाम ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की

डीजल व पेट्रोल पर 8 रुपये लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रावधान

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 23 मार्च

कर दायरे को व्यापक बनाने और कर चोरी रोकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीजल और पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के प्रावधान और विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल कर के साथ 40 से अधिक बदलावों के साथ वित्त विधेयक आज लोकसभा में पेश किया। कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण लोकसभा ने चर्चा के बिना विधेयक को पारित कर दिया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए विधेयक में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क प्रति लीटर 3 रुपये बढ़ा दिया था जिससे सरकार को सालाना 39,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसमें 2 रुपये का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और एक रुपये सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर शामिल था। इस बढ़त से पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। अब इसे पेट्रोल पर 18 रुपये और डीजल पर 12 रुपये कर दिया गया है। वित्त विधेयक की आठवीं अनुसूची में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है।

भारत में कारोबार कर रहीं चीनी कंपनियों अलीएक्सप्रेस, शीन और क्लब फैक्टरी जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को झटका देते हुए सरकार ने विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर 2 फीसदी डिजिटल कर लगा दिया है। यह प्रावधान 1 अप्रैल से लागू होगा और इन कंपनियों को हर तिमाही के अंत में टैक्स देना होगा।

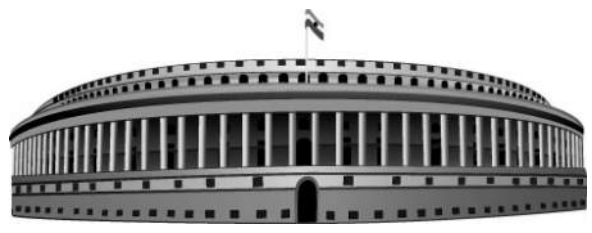

वित्त विधेयक में 40 से अधिक संशोधन

- पेट्रोलियम पर 8 रुपये लीटर उत्पाद शुल्क लगा सकेगी सरकार
- प्रवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर 2 प्रतिशत इक्वलाइजेशन लेवी
- प्रवासी भारतीयों के लिए 15 लाख रुपये तक आमदनी पर मिलेगी कर छूट
- एलआरएस रेमिटेंस पर टीसीएस छूट 5 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत
- चूककर्ताओं के लिए नकद निकासी पर ज्यादा टीडीएस

एकेएम ग्लोबल में पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर डिजिटल कर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि इस बारे में दुनिया में आम सहमति नहीं बन जाती है। उन्होंने कहा, 'दिलचस्प बात है कि यह विदेशी कंपनियों द्वारा प्रवासियों को की गई आपूर्ति पर भी लागू होगा। इससे अनुपालन में मुश्किल आएगी।'

एएमआरजी एसोसिएट्स में पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि वित्त विधेयक में किए गए प्रावधानों से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा और खासकर चीन की ऑनलाइन कंपनियों की ओर से आ रहे सामान पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा, 'देश की सुस्ताती अर्थव्यवस्था को चीन की विनिर्माण, वितरण और ई-कॉमर्स कंपनियों से बचाने की जरूरत है जिनकी नजर सस्ते सामान की चाह रखने वाले भारतीय बाजारों पर रहती है।'

संशोधनों में प्रवासियों के लिए आय पर कर छूट की सीमा 15 लाख रुपये की गई है। बजट 2020 में किए गए संशोधनों के मुताबिक केवल उन्हीं भारतीयों पर कर लगेगा जो 120 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हैं और जिनकी पिछले साल आय (विदेशी स्रोतों से आय के अलावा) 15 लाख रुपये से अधिक रही। शार्दुल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर अमित सिंघानिया ने कहा पात्र प्रवासियों के लिए नियमों में छूट दी गई है। जिन लोगों की देश में आय 15 लाख रुपये से कम होगी, उन्हें इसका फायदा होगा। यह स्वागतयोग्य कदम है लेकिन यह सीमा थोड़ा कम है।

वित्त विधेयक संसद में बगैर चर्चा के पारित

अर्चिस मोहन
नई दिल्ली, 23 मार्च

सरकार ने वैश्विक आपदा कोविड-19 को देखते हुए आज संसद का बजट सत्र के सत्रावसान का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों में वित्त विधेयक 2020 बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। कोरोनावायरस के प्रसार को देखते हुए सदन की बैठक के समय को कम किया गया है, जो 3 अप्रैल तक चलने वाला था।

सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि राज्यों में शासन संभाल रहे विपक्षी दल के नेताओं से कहा गया है कि वित्तीय पैकेज पर काम चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बने आर्थिक कार्यबल ने साझेदारों के साथ बैठक की और पैकेज की घोषणा पर विचार किया।

कांग्रेस ने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाणिज्य मंत्री और वाणिज्य सचिव को पद से हटाएं, जिन्होंने वेंटिलेटर, सर्जिकल मास्क, फेस मास्क, मास्क के कच्चे माल के निर्यात की अनुमति 19 मार्च तक जारी रखा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 'डब्ल्यूएचओ ने वेंटिलेटर और मास्क का स्टॉक रखने की सलाह दी थी, इसके बावजूद ऐसा क्यों किया गया.. इसके निर्यात की अनुमति क्यों दी गई? किसके कहने पर ऐसा किया गया? यह आपराधिक षडयंत्र है।'

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह हमारे अपने डॉक्टरों, नर्सों, मरीजों के खिलाफ किया गया अपराध है, जो इन चीजों की भारी कमी के संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने 10 गुना ज्यादा दाम पर 19 मार्च तक मास्क और वेंटिलेटर के निर्यात की अनुमति दी।

राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में इस सत्र के दौरान 76 प्रतिशत काम हुआ और 12 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने कहा कि बजट सत्र का प्राथमिक मकसद आर्थिक वृद्धि को लेकर कार्रवाई और 2020-21 के विकास पर चर्चा करना था।

नायडू ने कहा कि कोरोनावायरस के वैश्विक प्रसार ने अफरातफरी मचा ही है और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर इसका असर पड़ा है, भारत भी इसका अपवाद नहीं है। सदन ने वित्त विधेयक वापस भेज दिया क्योंकि यह धन विधेयक था। नायडू ने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अनुपस्थित रहने के लिए छुट्टी मांगी है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है।

विपक्षी दलों ने आपदा के समय सरकार की विफलता को लेकर सरकार की आलोचना जारी रखी। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि संसद बंद करना ही एकमात्र काम नहीं है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने देरी की है। उनकी सरकार ने डब्ल्यूएचओ के कोविड-19 पर जारी दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन किया है, जिसने मास्क, रेस्पाइरेटर्स, सर्जिकल गाउन आदि का भंडारण करने को कहा था। विपक्षी नेताओं ने सुझाव दिया कि विवेकाधीन कोष की राशि का इस्तेमाल वेंटिलेटर के लिए किया जाना चाहिए।

बीएस सूडोकू 3696 | परिणाम संख्या 3695

2	9				4	6		3
4					7		8	
	1	6						
	6					7		
	8		9		5		6	
		3					4	
						2	5	
	2		4					7
5		1	2				9	6

5	3	4	2	1	9	8	6	7
8	9	7	6	3	5	1	2	4
6	1	2	4	8	7	5	3	9
3	6	5	8	4	1	7	9	2
4	2	1	9	7	6	3	8	5
9	7	8	5	2	3	4	1	6
1	5	3	7	6	2	9	4	8
7	8	6	3	9	4	2	5	1
2	4	9	1	5	8	6	7	3

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान ★★☆☆☆

चौहान चौथी बार मप्र के मुख्यमंत्री

बीएस संवाददाता
भोपाल, 23 मार्च

शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सोमवार देर शाम अपना नेता चुन लिया। विधायक दल की बैठक में दिल्ली के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सेदारी की। इसके साथ ही उनका चौथी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। वह चार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले राजनेता हैं।

इससे पहले शिवराज सिंह चौहान 2005, 2008 और 2013 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। परंतु पिछले दिनों तेजी से बदले घटनाक्रम में मुख्यमंत्री कमल नाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार उस समय गिर गई जब वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 22 विधायकों ने त्यागपत्र दे दिया। सिंधिया और उनके समर्थक विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

शिवराज सिंह चौहान

प्रदेश में शीघ्र ही उपचुनाव कराए जाएंगे। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा को 9 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, तभी विधानसभा में पार्टी को बहुमत हासिल हो सकेगा। फिलहाल पार्टी के पास 107 विधायक हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 31

आपातकालीन पैकेज

दुनिया भर की सरकारें कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई के कारण मची उथलपुथल और उससे होने वाले आर्थिक नुकसान से निपटने की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। अमेरिका, जहां हाल के दिनों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है और जहां की स्वास्थ्य सेवाओं में यूरोप से अधिक खामियां हैं, वहां आर्थिक पैकेज भी उसी अनुपात में भारी-भरकम है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक लैरी कडलो ने कहा है कि पैकेज का तीसरा चरण, जिस पर अभी चर्चा चल रही है, वह एक लाख करोड़ डॉलर के मूल विधेयक से ज्यादा हो सकता है, यानी तकरीबन 2 लाख करोड़ डॉलर के आसपास। बल्कि यह अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद के 10 फीसदी तक पहुंच सकता है।

अन्य देशों ने भी अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दी है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने यूरो क्षेत्र में बैंक ऋण के लिए सहायता देने की बात कही है। इस दौरान वह पूंजी आवश्यकता को शिथिल करेगा और बैंकों को दीर्घावधि का ऋण देगा। यूरोप की विभिन्न सरकारों ने भी इसमें दखल दिया है। जर्मनी में चांसलर एंगेला मर्केल अपने चिकित्सक के कारण कोरोनावायरस के संपर्क में आने के बाद स्व-पृथक्करण में चली गई हैं। जर्मनी ने अपने प्रमुख सरकारी बैंक को कंपनियों को 600 अरब डॉलर से अधिक राशि देने के लिए अधिकृत किया है। फ्रांस में छोटे कारोबारों के लिए इससे करीब आधे आकार का पैकेज तैयार किया जा रहा है। अन्य देशों में भी ऐसे ही लक्षित कदम उठाए हैं। दक्षिण कोरिया ने विशेष ध्यान खींचा है। उसने छोटे कारोबारों और छंटनी किए गए कर्मचारियों के लिए 10 अरब डॉलर के भीतर का पैकेज जारी किया है।

भारत ने देरी से कदम उठाया है जबकि देश में कोरोनावायरस का प्रभाव उसके सामने काफी समय पहले से ही स्पष्ट था। आर्थिक क्षति के आकार को लेकर भी भारत में कोई व्यापक सोच देखने को नहीं मिल रही है। जबकि प्राथमिक तौर पर हमें आम परिवारों और कॉर्पोरेट क्षेत्र को होने वाली नकदी की बाधा से निपटना होगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सुझाव दिया है कि करीब 5 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाना चाहिए। यह राशि जीडीपी के 2.5 फीसदी के बराबर है। परंतु यह न्यूनतम पैकेज होना चाहिए। यह तो अनिवार्य रूप से किया ही जाना चाहिए। इस पैकेज को बेहद सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए ताकि यह उन लोगों के लिए सब्सिडी में तब्दील न हो जाए जिन्हें वास्तव में सब्सिडी की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि यह वैसी ही गलती होगी जैसी कि अमेरिका में हो रही है और इसी के कारण उसका भारी भरकम प्रोत्साहन पैकेज कांग्रेस से पारित होने में दिक्कत हो रही है। भारत में नोटबंदी का अनुभव यह दर्शा चुका है कि कैसे अर्थव्यवस्था के संवेदनशील तबके को सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। इस तबके में असंगठित क्षेत्र, दैनिक मजदूर और शामिल हैं। ये किसी भी तरह पैकेज से बाहर न रह जाएं।

चीन की सरकार ने सन 2008 की तरह किसी बड़े वित्तीय पैकेज की घोषणा नहीं की है लेकिन उसने कुछ औपचारिक कारोबारों के लिए बैंक ऋण की अवधि बढ़ाकर मदद की है। इसके अलावा किराये जैसे अन्य जरूरी भुगतान को निलंबित किया गया है। सरकार को इस व्यवस्था पर नजर रखनी चाहिए ताकि औपचारिक क्षेत्र को बचाया जा सके। जबकि उसे यह भी तय करना चाहिए कि पैकेज की अधिकांश राशि असंगठित और कमजोर तबके पर खर्च हो। सरकार को न केवल बड़ा सोचने की आवश्यकता है बल्कि उसे अपनी योजना को लचीला रखना होगा ताकि जरूरत के मुताबिक तेजी से बदलाव लाया जा सके।

अजय मोहंती

विश्व अर्थव्यवस्था पर दबाव से अस्थिर बाजार

वैश्विक वित्तीय बाजारों में तनाव के कारण बाजार में अस्थिरता है। कोरोनावायरस का आर्थिक प्रभाव और तेल कीमतों में गिरावट भी अनिश्चितता की वजह हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं **नीलकंठ मिश्रा**

वैश्विक बाजारों में उथलपुथल मची है। थोड़ी बहुत अस्थिरता आम है: हर एक दो वर्ष में ऐसे हालात बनते हैं जब जोखिम वाली परिसंपत्तियों में बिकवाली होती है और कीमतों में गिरावट के बाद उनकी खरीद की उपयोगिता को लेकर सवाल जवाब किए जाते हैं। परंतु बीते एक महीने में कीमतों में बदलाव की गति और उसका परिमाण एक दशक पहले के ऐसे ही उथलपुथल वाले महीनों की याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि वित्तीय बाजार तीन बड़े सवालों के जवाब देने में संघर्ष कर रहा है और हमेशा की तरह समस्या से अधिक दिक्कत इस बात से होती है कि उनके प्रभाव में इजाफा अनिश्चित रहता है। सबसे पहला है वैश्विक आर्थिक उत्पादन पर कोरोनावायरस का प्रभाव, दूसरा तेल कीमतों में तेज गिरावट का असर और तीसरा उपरोक्त दोनों कारणों से वैश्विक वित्तीय बाजार में तनाव।

क्रेडिट सुइस के वैश्विक अर्थशास्त्री और मुद्रा बाजार के नीतिकारों ने पहले चीन और उसके बाद शेष विश्व में कोरोनावायरस के कारण हुई विसंगतियों से फंडिंग के दबाव को शिथिल किया है। कामकाज में गिरावट आने से मुद्रा की गति भी धीमी होती है: उपभोक्ता अपने घरों में रुक जाते हैं और उत्पादन में धीमापन आता है क्योंकि कलपुर्जों की आपूर्ति कम होती है। कुछ लोग कर्ज ले सकते हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र के ज्यादातर लोगों के लिए आय और खपत दोनों में तेजी से गिरावट आती है। अन्य परिवार तथा कुछ फर्म के पास नकदी संतुलन बेहतर है क्योंकि वे बाहर नहीं जा रहे। ये परिवार सामान्य से कम खर्च कर रहे हैं।

यह वैश्विक स्तर पर हो रहा है। विभिन्न देशों में उनके केंद्रीय बैंक इस समस्या को हल कर सकते हैं लेकिन वैश्विक भुगतान जो प्राय: अमेरिकी डॉलर में होते हैं, वहां अमेरिकी फेडरल रिजर्व को कदम उठाना होगा। पिछले सप्ताह बुधवार को उसने कदम उठाया और असीमित नकदी की आपूर्ति सुनिश्चित की लेकिन उससे पहले संकेत ऐसे थे जो सन 2008 के संकट के शुरुआती दौर की याद दिला रहे थे। ये आखिरी बार सन 2011 में ग्रीस के संकट के समय नजर आए थे। उदाहरण के लिए अमेरिकी सरकारी बॉन्ड की मांगी जाने वाली कीमत और खरीदार द्वारा चुकाने की इच्छा रखी जाने वाली कीमत के बीच का अंतर रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गया। नकदीकृत प्रतिभूतियों के मामले में यह अंतर आमतौर पर कम रहा है और अमेरिकी प्रतिभूतियां विश्व की सर्वाधिक नकदीकृत प्रतिभूति हैं। फेडरल रिजर्व के कदम अब तक गैर अमेरिकी फर्म के लिए मददगार नहीं रहे हैं। ऐसे में 2008 के संकट के दौरान इस्तेमाल की गई स्वैप की व्यवस्था दोबारा शुरू करनी होगी।

नकदी की इसी कमी के कारण उभरते बाजारों के इक्विटी फंड से पूंजी बाहर गई। गत 30 दिन में 36 अरब डॉलर की राशि बाहर गई। यह 2008 के संकट से बहुत ज्यादा है। ब्राजील और तुर्की के बाजार जो ऐतिहासिक रूप से फंड के बाहर जाने को लेकर शंकालु रहे हैं, उनका रिकॉर्ड सबसे कमजोर रहा है। भारत में पिछले महीने चार अरब डॉलर (पिछले एक सप्ताह में दो अरब डॉलर) की राशि का बाहर जाना 2008 के खराब दौर के काफी करीब है। हालांकि इस बार बाजार पूंजीकरण का अनुपात कुछ बेहतर है।

कुछ नियामकीय कदम मसलन कोरिया जैसे बाजारों द्वारा शॉर्ट सेलिंग पर प्रतिबंध भी निकट भविष्य में मददगार हो सकते थे लेकिन ये ज्यादा लंबे नहीं चले क्योंकि बीते एक महीने में काफी सुधार देखने को मिला।

हमें यह याद रखना चाहिए कि मुख्य जोखिम बरकरार हैं। वायरस को थामने के लिए यात्राओं पर लगे प्रतिबंध और सार्वजनिक समारोहों को रद्द करने से आय को हुए नुकसान का कोई निदान नहीं है। यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। कारों और टेलीविजन जैसी वस्तुओं की बिक्री में देरी के उलट सेवाओं से गंवाई गई आय हमेशा के लिए नहीं जाती। केवल कम ब्याज दर से इसका हल नहीं मिलेगा। कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास यह क्षमता होगी जो वैसा प्रोत्साहन दे सकें जैसा हॉन्गकॉन्ग ने दिया (हर वयस्क को 10,000 डॉलर)।

इटली या जर्मनी के सॉवरिन बॉन्ड प्रतिफल के बीच का अंतर बीते कुछ सप्ताह में बढ़ा है। यह इस बात को दर्शाता है कि बाजार में इटली में बढ़ते राजकोषीय घाटे को लेकर नए सिरे से आशंका बढ़ रही है। कोरोनावायरस के असर की आशंका को देखते हुए यह अपरिहार्य नजर आ रहा है। यूरोपीय संघ के अन्य देशों में भी ऐसा हो सकता है।

तेल कीमतों में तेज गिरावट अनिश्चितता और बढ़ाती है। विश्व स्तर पर तेल कीमतें कुछ और नहीं बल्कि कीमत का उत्पादक से उपभोक्ता तक स्थानांतरण हैं। कम कीमत से उत्पादक प्रभावित होते हैं और उपभोक्ता लाभान्वित। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 30 डॉलर की गिरावट होने पर भारत को सालाना 42 अरब डॉलर की बचत होती है। यानी जीडीपी का करीब 1.4 फीसदी। यदि करों में इजाफा नहीं किया जाता तो इसका आधा हिस्सा उपभोक्ताओं को मिलता और खपत बढ़ाने में मदद मिलती जो इस वक्त जरूरी था। एक बार कर में तब्दील किए जाने के बाद सरकार के लिए इसे वितरित करना मुश्किल हो जाता है।

कई तेल निर्यातक देशों के लिए आय में कमी आई है। भविष्य के तेल खनन के लिए पूंजीगत व्यय में कमी और तेल उत्पादकों को ऋण देने वालों को उत्पन्न जोखिम जैसी बातें आसानी से बढ़ सकती हैं। बड़ा जोखिम यह है कि कई छोटे उत्पादक (लेकिन जहां तेल उत्पादन राष्ट्रीय राजस्व का बड़ा हिस्सा है) देशों में सरकार कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने से भी चूक सकती है। बड़े उत्पादक बीते दो दशक में अपने लिए बचाव तैयार कर चुके हैं और अगर कम कीमतें अगले कुछ वर्ष तक जारी नहीं रहीं तो उन्हें समस्या नहीं होगी।

बाजार को मौजूदा हालात से उबरने में कुछ वक्त लग सकता है। वैश्विक उथलपुथल के मौजूदा दौर में भारत जैसे वित्तीय तंत्र में क्षमता की कमी है और प्रभावी ब्याज दर नॉमिनल वृद्धि दर से अधिक। इसके अलावा उपभोक्ता और निवेश रुझान कमजोर हैं। इन्हें हल करना आवश्यक है। आने वाले सप्ताह और महीनों के दौरान नीति निर्माताओं को तेज और सुसंगत कदम उठाने होंगे। ऐसे में चुनौतियों को अवसरों में तब्दील किया जा सकता है।

कोरोनावायरस के दौर में पानी का सवाल

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

विश्व जल दिवस 22 मार्च को था। कोरोनावायरस से लड़ने के लिए हमने अर्थव्यवस्थाओं को लॉकडाउन कर दिया है और हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे लिए साफ, सुरक्षित और सर्वसुलभ का मुद्दा कितना अहम है। आज इस वैश्विक महामारी से बचाव का एकमात्र तरीका यही है कि हम बार-बार अपने हाथ धोएं। हर बार हमें 20 सेकंड तक हाथ धोने की जरूरत है। सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य के लिए आज भी साफ पानी दुनिया में सबसे अहम एहतियाती उपाय है। ऐसे में आज जब हम कोरोनावायरस के रूप में नए वैश्विक दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं तो इस लड़ाई में जीत के लिए पानी की उपलब्धता सबसे कारगर हथियार होगा।

हममें से अधिकांश लोग इस बात से राहत महसूस करेंगे कि हमें अपने नलों से पानी मिल सकता है और अगर यह पानी साफ नहीं है तो हम बोतलबंद पानी खरीदकर पी सकते हैं। हम पानी की सरकारी व्यवस्था से निजी व्यवस्था का रुख कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम दो बातें भूल जाते हैं। पहली यह कि जो पानी हम खरीदते हैं, वह भी अधिकांश मामलों में सरकारी स्रोतों से ही आता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम बोतलबंद पानी भी खरीदते हैं तब भी हम मूत्र के रूप में पानी ही निकालते हैं। जितना ज्यादा पानी हम इस्तेमाल करेंगे, उतना ही जलमल हम पैदा करेंगे। अगर हमने इस जलमल को नहीं रोका और इसका शोधन नहीं किया तो इससे जल प्रदूषण बढ़ेगा और जलस्रोतों का क्षरण होगा। इससे दूषित जल के मामले में हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी।

जल संकट हमारा स्वास्थ्य संकट है। कोरोनावायरस को ही लीजिए। इसके संक्रमण से बचने और इसके विषाणु को मारने के लिए 20 सेकंड तक हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। यानी हर बार हाथ धोने के लिए आपको मोटे तौर पर 1.5 से 2 लीटर पानी की जरूरत है। बार-बार हाथ धोने का मतलब है कि हर व्यक्ति को दिनभर में 15 से 20 लीटर पानी की जरूरत होगी। इस तरह पांच लोगों के परिवार को हाथ धोने के लिए रोजाना 100 लीटर पानी की जरूरत होगी। मान लीजिए कि आप हाथ पर साबुन रगड़ते समय नल खुला नहीं छोड़ते हैं, फिर भी पानी की खपत बहुत ज्यादा होगी। लेकिन विषाणु को दूर रखने और आपके स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है।

यह अपने आप में चुनौती है। भारत और विकासशील देशों में बड़ी संख्या में लोगों की पानी तक पहुंच नहीं है, पीने लायक पानी तो दूर की बात है। तो फिर वे खुद को विषाणु से कैसे बचा पाएंगे? यह वैश्विक महामारी हमारे लिए सबक है कि हम इस शृंखला की सबसे कमजोर कड़ी हैं। इस महामारी से बचने के लिए जरूरी है कि हर किसी की जन स्वास्थ्य तक पहुंच हो ताकि कोई भी इससे वंचित न रहे और विषाणु का वाहक न बने। पानी के साथ भी यही मामला है। अगर लोगों की साफ पानी तक पहुंच नहीं होगी तो फिर वे बीमारी के प्रसार को रोकने में विफल रहेंगे। इस महामारी पर काबू नहीं किया जा सकेगा। इसलिए, साफ पानी तक पहुंच न केवल मौलिक अधिकार है बल्कि बीमारियों को रोकने और थामने के लिए भी यह बेहद जरूरी है।

अच्छी खबर यह है कि हमें भली भांति पता है कि हमें क्या करने की जरूरत है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि पानी एक अक्षय स्रोत है और हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि बारिश की हर एक बूंद को बचाया जाए, स्थानीय स्तर पर जल भंडारण की व्यवस्थाएं की जाएं, कम पानी की खपत वाली फसलों का उपभोग किया जाए और अपशिष्ट जल की हर बूंद का इस्तेमाल किया जाए। अब हमें इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है।

लेकिन मौजूदा वैश्विक महामारी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हर किसी को पानी उपलब्ध हो। इसका मतलब है कि हमें अपनी जल और अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं में जरूरी बदलाव करने होंगे ताकि वे सभी के लिए किफायती हों। मौजूदा व्यवस्थाएं इतनी महंगी हैं कि कुछ ही लोग इनको वहन कर सकते हैं। पानी लाने के लिए पाइपलाइन जितनी लंबी होगी, आपूर्ति का खर्च उतना अधिक होगा। इससे जल वितरण तंत्र की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि हमारे शहरों में बड़ी संख्या में लोगों के पास नल से जल आपूर्ति की सुविधा नहीं है। उन्हें टैंकरों से पानी मिलता है या वे पेयजल और दूसरी जरूरतों के लिए प्रदूषित जल स्रोतों पर निर्भर हैं। इससे स्वास्थ्य पर उनका खर्च बढ़ जाता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। पानी की आपूर्ति की लागत जितनी अधिक होगी तो जल निकाय के पास अपशिष्ट जल की निकासी और शोधन के लिए धन नहीं बचेगा। इस तरह गंदा पानी हमारे जल स्रोतों में मिल जाएगा और इसे साफ करने की लागत बहुत अधिक हो जाएगी।

हमारे लिए ज्यादा जलमल शोधन संयंत्र बनाने की योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें आपूर्ति पर नए सिरे से डिजाइन करना होगा ताकि हम पाइपलाइन की लंबाई में कमी कर सकें। इसके लिए हमें स्थानीय स्तर पर पानी के भंडारण की व्यवस्थाओं में निवेश करना होगा। हमें पानी के उपयोग को कम करके मांग को फिर से डिजाइन करना होगा ताकि हम पानी की बरबादी को कम कर सकें। साथ ही हमें अपशिष्ट जल प्रबंधन को फिर से डिजाइन करने की जरूरत है ताकि हम अपशिष्ट पानी का शोधन करके खाद को जमीन को वापस कर सकें और नदियों में साफ पानी डाला जा सके। लेकिन लब्बोलुबाब यह है कि यह व्यवस्था सभी के लिए सस्ती होनी चाहिए, अन्यथा यह किसी के लिए टिकाऊ नहीं होगी।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवॉयरनमेंट से संबद्ध हैं।)

कानाफूसी

दिग्विजय की गलती!

ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद उनके समर्थक रहे विधायकों ने भी पहले इस्तीफा दिया और फिर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को लेकर विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मुकेश नायक का कहना है कि मौजूदा संकट सिंह के कारण ही उत्पन्न हुआ। एक अन्य नेता ने कहा कि सिंह की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा ने पार्टी की सरकार गिराने की राह बनाई। उन्होंने कहा कि सिंह राज्यसभा के लिए पार्टी की पहली प्राथमिकता में थे। इस बात ने पहले से नाराज सिंधिया को और चिढ़ा दिया। सिंधिया सिंह और कमल नाथ की कार्यशैली से पहले ही नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद से सिंधिया राज्यसभा सीट के लिए प्रयासरत थे लेकिन प्रदेश में पार्टी का सीमित बहुमत देखते हुए दूसरे प्रत्याशी के राज्यसभा पहुंचने पर संशय उत्पन्न हो गया था। बहरहाल, सिंधिया ने भाजपा की सदस्यता ले ली और अब वह उसकी ओर से राज्यसभा के प्रत्याशी हैं। उसका परिणाम प्रदेश में कांग्रेस सरकार के पतन के रूप में सामने आया।

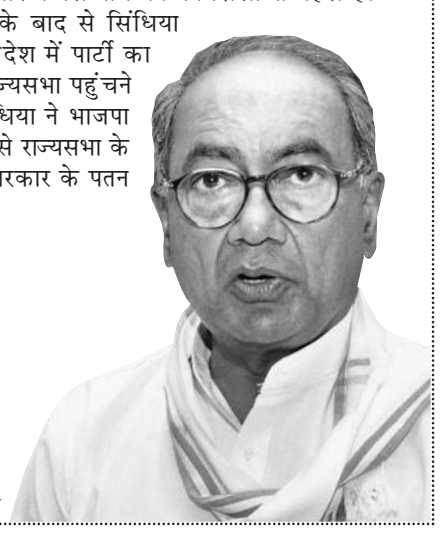

दिग्विजय सिंह

आपका पक्ष

कोरोना के प्रति लापरवाही न बरतें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस को भारत में खत्म करने के उद्देश्य से 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। अगर प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की तरह दूसरे देश खासतौर पर चीन ने ऐसी समझदारी दिखाई होती और अपने देश में कोरोना के शिकार मरीजों की पहचान कर अस्पताल में रखा होता तो यह वायरस चीन के साथ अन्य किसी भी देश के लिए आफत नहीं बनता। भारत में कोरोनावायरस फैलने का मुख्य कारण दूसरे देशों से आने वाले लोग हैं। ऐसे लोग ही कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अगर इन लोगों ने अपनी जांच कराई होती तो भारत में यह वायरस नहीं फैलता। पंजाब में अभी भी हजारों में ऐसे एनआरआई हैं जो हाल ही में विदेश यात्रा कर लौटे हैं। ऐसे लोग लापता हैं अथवा अपनी जांच कराने से बच रहे हैं। अगर लोग समय रहते अभी भी जांच नहीं कराते हैं तो हो सकता है कि वह

दिल्ली को लॉकडाउन करने के बाद गाजियाबाद-दिल्ली की सीमा पर अवरोधक लगाया गया

संक्रमित हों। नेता, अभिनेता या फिर आम लोग जो भी हाल में विदेश यात्रा कर लौटे हैं उन्हें और उनके संपर्क में आने वाले सभी को अपनी जांच करानी चाहिए। वर्ष 1918 में भारत में स्पैनिश फ्लू (इन्फ्लुएंजा) ने महामारी का रूप लिया था। इसकी चपेट में आने से लाखों-करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। कुछ जानकार यह भी बताते हैं कि महामारी से देश की जनसंख्या लगभग सात फीसदी घट गई थी। कोरोनावायरस एक बार फिर से देश में महामारी के रूप में पैर पसार चुका है। हालांकि वर्ष 1918 और आज के समय में भारत में चिकित्सा पद्धति और इस क्षेत्र में काफी तरक्की की है। आज मीडिया का भी जाल बिछ चुका है कि देश को महामारी से जल्द मुक्त किया जा सकता है। लेकिन यही तभी संभव है जब लोग समझदारी से काम लें। देश में कोरोना का कहर नहीं बढ़े इसके लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। कोरोना को तभी हराया जा सकता है जब तक देश का हर नागरिक इसके लिए अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं कर लेता।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सोशल मीडिया में अफवाहों से सावधान

सोशल मीडिया में कोई द्वारपाल नहीं होता है। इसी वजह से उन्माद फैलाने वाले लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया अफवाहों का तंत्र बन चुका है। इसमें प्रसारित की जाने वाली सामग्री के माध्यम से देश में हिंसा और अलगाव फैलाया जा रहा है, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा युवा हैं। वर्तमान में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 56 करोड़ से अधिक है। इतनी बड़ी संख्या में इंटरनेट उपभोक्ता होने के नाते भारत इंटरनेट बाजार के लिहाज से एक अच्छा देश है। भारत में सोशल मीडिया के प्रमुख प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और ट्विटर आदि हैं। इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। देश में कोरोनावायरस को लेकर भी काफी अफवाहें फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया के जरिये उन्माद फैलाना, भड़काना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, झूठी खबरों को फैलाना और मानहानि करना वर्तमान में अधिक हो रहा है। अत: यह बेहद जरूरी है कि सोशल मीडिया के लिए सख्त कानून बनाया जाए।

गौतम एसआर, खंडवा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

चीनी निर्यात में आएगी गिरावट

रॉयटर्स
नई दिल्ली, 23 मार्च

वर्ष 2019/20 में भारत का चीनी निर्यात 45 लाख टन रहने की संभावना है जो पिछले अनुमान की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम है। उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोनावायरस के प्रसार से मिलों के लिए वैश्विक बिक्री गैर-लाभकारी रह गई है जिसकी वजह से वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है।

दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक से कम निर्यात की वजह से वैश्विक कीमतों को मदद मिल सकती है। ये कीमतें 12 फरवरी के ऊंचे स्तर से लगभग एक-तिहाई गिर चुकी हैं और इससे ब्राजील जैसे प्रतिस्पर्धियों को निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है।

> चीनी निर्यात में पूर्व के अनुमान की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आने के आसार

वैश्विक कीमतों में ताजा गिरावट के बाद निर्यात को लेकर समानता नहीं दिख रही है। नैशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनावरे ने रॉयटर्स को बताया कि इस कीमत स्तर पर नए सौदे नहीं होंगे।

कई वर्षों तक गन्ने की बंपर पैदावार और शानदार चीनी उत्पादन से भारतीय चीनी कीमतों पर दबाव बना हुआ था जिससे मिलों को किसानों को रकम चुकाना मुश्किल हो रहा है।

उन पर कर्ज का बोझ घटाने और बढ़ती इन्वेंट्री में कमी लाने के लिए सरकार ने 30 सितंबर को समाप्त हो रहे 2019/20 सीजन में 60 लाख टन निर्यात के लिए 10,448 रुपये प्रति टन की सब्सिडी स्वीकृत की है।

अनाज-दाल पर बंदी का असर

सब्जियों, खाद्य तेल, अनाज और दलहन समेत कई बाजारों और उनके प्रसंस्करण से संबंधित कंपनियों को जूझना पड़ रहा है समस्याओं से

राजेश भयानी
मुंबई, 23 मार्च

जरूरी जिंस बाजारों, इनके आयातकों, प्रोसेसरों को श्रमिक किल्लत और परिवहन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों, खाद्य तेल, अनाज और दलहन समेत कई बाजारों और उनकी प्रोसेसिंग से संबंधित कंपनियों को या तो श्रमिक उपलब्ध नहीं होने से, या परिवहन संसाधनों से जुड़ी समस्याओं की वजह से कारोबारी दबाव से जूझना पड़ रहा है। बाजार के दिग्गजों का मानना है कि यदि इस तरह की दिक्कतें लंबे समय तक बनी रहीं, तो उपलब्धता अन्य बड़ी समस्या साबित हो सकती है।

पिछले कुछ दिनों से मुंबई में अनाज की ढुलाई दोगुनी बढ़कर प्रतिदिन एक लाख बोरे (30 किलोग्राम वजन वाले) हो गई। अब, कई राज्यों में लॉकडाउन किए जाने के बाद ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि वे उत्पादन केंद्रों से अनाज उठा सकते हैं, पर वापसी में जब वे खाली जाते हैं तो यह आशंका बनी रहती है कि वे यह साबित करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे कि उनके वाहन को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था और इस वजह से उन्हें बीच में ही रोका जा सकता है। कई ट्रांसपोर्टर चालक उपलब्ध नहीं होने की समस्या बता रहे हैं। मुंबई के थोक बाजार में, 10 दिन के लिए अनाज का स्टॉक उपलब्ध है और कारोबारियों का मानना है कि परिवहन समस्याएं इस अवधि के अंदर दूर हो सकती हैं।

नवी मुंबई की अनाज मंडी मंगलवार तक बंद है और यह बुधवार को भी बंद रह सकती है, क्योंकि कोरोनावायरस के डर से श्रमिक अपने घर चले गए हैं। नवी मुंबई एपीएमसी के निदेशक नीलेश वीरा ने कहा, 'श्रमिकों की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। हमने सरकार से श्रमिकों को वापस लाए जाने के प्रयास में उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर, मास्क आदि मुहैया कराने को कहा है, लेकिन अब तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है।'

न्यू मुंबई वेजीटेबल मार्केट के एक प्रतिनिधि ने कहा कि उनका बाजार कल खुलने की संभावना है, पर श्रमिकों के अभाव से सड़क किनारे कई खुदरा सब्जी विक्रेता इस व्यवसाय से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि थोक बिक्री बाजार में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और इसके उठाव के लिए कारोबारियों का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति और वितरण से संबंधित समस्या राज्य में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

दालों की मांग बनी हुई है, क्योंकि पोल्ट्री उत्पादों के बजाय दालों की मांग बढ़ी है और चने की कीमतें बढ़ रही हैं। चने को 'दालों का राजा' के तौर पर जाना जाता है। हालांकि कई दाल मिलों को समान समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कुछ केंद्रों में श्रमिक नहीं आ रहे हैं या ट्रांसपोर्टर माल नहीं उठा रहे हैं। सरकारी कोटे के तहत दालों का आयात किया जा चुका है और यह सीमा शुल्क अधिकारियों की मंजूरी के लिए पड़ा हुआ है। एक आयात ने कहा कि इस संबंध में सीमा शुल्क विभाग ज्यादा सक्रियता के साथ काम नहीं कर रही है जिससे समस्या बढ़ रही है।

इंडिया पल्सेज ऐंड ग्रेन्स एसोसिएशन के वाइस-चेयरमैन बिमल कोठारी ने कहा, 'मेरा मानना है कि आज लॉकडाउन का पहला दिन है और इसलिए व्यापार से संबंधित समस्याएं कोरोनावायरस की गंभीरता को देखते हुए काफी कम हैं। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिन में हालात सामान्य हो जाएंगे।'

वहीं आटा मिलें भी इससे अलग नहीं हैं और उन्हें भी इसी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। भारी मांग के बाद आटा मिलों को पूरी क्षमता के साथ परिचालन करना पड़ रहा है। एक आटा मिल का कहना है कि सबसे बड़ी आटा विक्रेता एफएमसीजी कंपनी के पास भारी मांग आ रही है, लेकिन उन्हें पैकिंग मैटेरियल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। उनकी समस्या यह है कि अधिकारी पैकिंग मैटेरियल को अनिवार्य जिंस के तौर पर मानने को तैयार नहीं हैं।

भारत अपने खाद्य तेल का तीन-चौथाई हिस्सा आयात करता है। लेकिन रुपये में गिरावट ने पिछले कुछ सप्ताहों में तेल को महंगा बना दिया है, जिससे इसकी मांग में भी कमी आई है।

बंदी के बाद बढ़ी दिक्कत

अपर्याप्त श्रमिक और परिवहन सुविधा में कमी के कारण बाजारों में कारोबारियों को झेलनी पड़ रही है कई प्रकार की दिक्कतें

आयातित दालों और खाद्य तेल को जांच संबंधी समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना

- मंडियों में जरूरी जिंसों की आपूर्ति प्रभावित हुई है
- श्रम की कम उपलब्धता और सामान पहुंचाने में ट्रांसपोर्टरों की आनाकानी हैं बड़ी समस्याएं
- ज्यादा मांग को देखते हुए आटा मिलें, दाल मिलें तेजी से परिचालन कर रही हैं

एमसीएक्स पर तांबा 4.6 प्रतिशत नरम, कच्चे तेल में भी फिसलन

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 23 मार्च

कोरोनावायरस के तेज प्रसार की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता के बाद मांग में कमी आने की आशंका से मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर तांबे की कीमत में 4.6 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई।

एमसीएक्स पर सबसे ज्यादा सक्रिय तांबा अनुबंध में बड़ी गिरावट देखी गई। लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) और शांघाई एक्सचेंजों पर गिरावट के बाद सोमवार को दिन के सत्र के अंत में एमसीएक्स पर यह अनुबंध 355 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। मार्च डिलिवरी का तांबा वायदा भी गिरकर 11 वर्ष के निचले स्तर पर आ गया। कोविड-19 मरीजों की संख्या में वृद्धि से देशों के बीच व्यापार प्रतिबंधों और बंद की वजह से इसमें यह बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

अन्य जिंसों में, अप्रैल डिलिवरी के लिए कच्चा तेल वायदा में लगातार गिरावट आई और सोमवार को यह 8.77 प्रतिशत तक की कमजोरी के साथ 1,768 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। सीसा, निकल, और जस्ता समेत अन्य प्रमुख धातुओं में भी गिरावट बरकरार रही और मांग प्रभावित होने की चिंता से इनमें लगभग 3.5 प्रतिशत तक की कमजोरी दर्ज की गई।

केडिया एडवायजरी के निदेशक अजय केडिया ने कहा, 'कोविड-19 महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर अनिश्चितता बढ़ी है। कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने राहत उपायों की घोषणा की है जिनसे संकेत मिलता है कि मांग से संबंधित आधार कमजोर बने रहने की आशंका है। हालांकि आपूर्ति के संदर्भ में, मौजूदा लॉकडाउन और कारोबार प्रतिबंधों का असर पहले ही दिख चुका है। कमजोर मांग और प्रमुख धातुओं और ऊर्जा को लेकर अनिश्चितताएं वैश्विक रूप से देखी जा रही हैं।' कच्चे तेल में कीमत युद्ध शुरू होने से कच्चे तेल की आपूर्ति भी बढ़ जाती है।

हालांकि सराफा सेगमेंट में, मजबूत बुनियादी आधार के बावजूद सोने की कीमतें हाजिर एवं वायदा बाजारों में कुछ नीचे आई हैं। लोकप्रिय जवेरी बाजार में सोना 1.5 प्रतिशत तक घटकर सोमवार को 40,556 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। हालांकि वायदा में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई। पारंपरिक बाजार में चांदी 1 प्रतिशत तक टूटकर 36,850 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अमेरिका द्वारा अतिरिक्त नकदी लगाए जाने की घोषणा के बाद कीमतों में सुधार देखा गया। शांघाई फ्यूचर एक्सचेंज (एसएचएफई) पर सबसे ज्यादा सक्रिय तांबा अनुबंध 8 प्रतिशत तक गिरकर 35,300 युहान प्रति टन पर कारोबार कर रहा था, जो 23 जून 2009 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। लेकिन ताजा बुकिंग की वजह से बाद में यह थोड़ा चढ़कर 37,080 युआन प्रति टन पर आ गया, जबकि एलएमई पर तीन महीने की डिलिवरी का तांबा 5.2 प्रतिशत तक की गिरावट के साथ 4,562 डॉलर प्रति टन पर आ गया।

एक विश्लेषक ने कहा, 'कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई देश अपने शहरों को लॉकडाउन कर रहे हैं और अन्य देशों के साथ व्यापार को बंद कर रहे हैं। इस महामारी से हजारों लोगों की मौत हुई है और लाखों की तादाद में संक्रमित हुए हैं। औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती आने से, धातुओं की मांग धीमी बनी रहने और इन्वेंट्री में इजाफा होने की आशंका है जिससे प्रमुख धातुओं पर दबाव बढ़ सकता है।' चीन के वुहान शहर में कोविड-19 की शुरुआत के बाद से तीन महीनों के दौरान सभी प्रमुख धातुओं, ऊर्जा और सराफा की कीमतें 10-50 प्रतिशत के बीच नीचे आई हैं।

दिलचस्प तथ्य यह है कि हीरा लाभकारी निवेश विकल्प के तौर पर उभरा है, जिसने वायदा में पिछले तीन महीनों में अच्छा प्रतिफल दिया है। हीरा वायदा दिसंबर के 3,350 रुपये प्रति कैरेट से बढ़कर अब 3,765 रुपये पर पहुंच गया है।

कोरोना का डर

- कमजोर मांग को लेकर वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से आई बड़ी गिरावट
- लंदन मेटल एक्सचेंज और शांघाई एक्सचेंजों पर गिरावट के बाद सोमवार को दिन के सत्र के अंत में एमसीएक्स पर तांबे का अनुबंध 355 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Mar 23	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,580.5	-10.8	1,835.1	-5.3
Copper	4,855.0	-21.1	5,413.6	-15.9
Nickel	11,370.0	-21.0	11,731.6	-21.9
Lead	1,673.5	-12.2	1,808.9	-18.5
Tin	14,500.0	-16.5	14,549.7	-19.1
Zinc	1,880.0	-18.5	1,966.2	-24.3
Gold ($/ounce)	1,525.4*	2.7	1,653.5	-0.7
Silver ($/ounce)	12.9*	-26.1	15.0	-23.6
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	25.4*	-61.7	28.2	-57.7
Natural Gas ($/mmBtu)	1.6*	-27.1	1.6	-30.2
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	182.2	-3.5	262.2	-13.8
Maize	182.4*	1.9	200.0	-33.1
Sugar	341.1*	-4.6	451.7	-6.6
Palm oil	552.5	-23.5	937.2	-17.1
Rubber	1,241.0*	-22.1	1,664.7	-9.5
Coffee Robusta	1,218.0*	-6.0	1,763.0	-5.6
Cotton	1,123.0	-25.8	1,257.6	-20.5

* As on Mar 23, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 76.3& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	77.7	38495
Oil and Oilseeds	319.3	88702
Spices	0.0	7
Metal(Mar 20)		
Metal- non ferrous	6612.2	31556
Metal- precious	14432.8	325
Oil and gas(Mar 20)		
Gas	2954.9	22599
Oil	10589.4	1889

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	104.9	93558
Grains	45.3	61070
Oil and Oilseeds	456.2	315355
Others	32.4	50945
Pulses	71.4	44440
Spices	48.2	16349

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Lead (May 29)	135.8	5.5
Crude Palm Oil (Mar 31)	667.4	2.7
Silver Mini (Apr 30)	35883.0	2.1
Silver (May 05)	35843.0	2.1
Silver Micro (Apr 30)	36706.0	2.0
Losers (* % Change)		
Cotton (Mar 31)	16310.0	-5.5
Kapas (Apr 30)	933.0	-4.5
Mentha Oil (Mar 31)	1130.4	-4.0
Cardamom (Apr 15)	2116.4	-3.0
Crude Oil (Apr 20)	1938.0	-2.1

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Soyabean Indore (Apr 20)	3652.0	3.8
Mustard Seed Rape Oil (Apr 20)	4103.0	3.6
Chana-Bikaner (Apr 20)	4110.0	3.6
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Apr 20)	786.6	3.3
Maize IndusNizamabad (Apr 20)	1319.0	3.0
CottonSeed Oil-Akola (Apr 20)	1824.0	2.4
Losers (* % Change)		
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	929.5	-4.6
Guar Seed 10 (Apr 20)	3236.0	-4.0
GuarGum 5T-Jodhpur (Apr 20)	4899.0	-4.0
Turmeric Nizamabad (Apr 20)	5522.0	-1.4

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Apr 15)	2116.4	-16.2
Menthol Oil Chandaus (Mar 31)	1130.4	-12.7
Cotton-Rajkot (Mar 31)	16310.0	-9.7
Zinc Mini Mumbai (Mar 31)	143.2	-7.8
Zinc Mumbai (May 29)	143.3	-7.7
Lead Min Mumbai (Mar 31)	131.9	-6.9
Kapas Surendranagar (Apr 30)	933.0	-4.2
Lead Mum (May 29)	135.8	-4.1
Copper Mum (Mar 31)	372.8	-4.0
Nickel Mumbai (Mar 31)	860.7	-3.5
Gold Petal-Mumbai (Mar 31)	3985.0	-3.5

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Jeera Unjha (Apr 20)	13700.0	0.3
Discount over spot price (In %)		
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Apr 20)	4899.0	-10.2
Coriander-Kota (Apr 20)	5884.0	-1.9
Soy Bean Indore (Apr 20)	3652.0	-1.3
Turmeric Nizamabad (Apr 20)	5522.0	-1.2

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	..............Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	107.....(107)
Aluminium ingots /kg	140.....(140)
Brass sheet cutting /kg	293.....(283)
Brass utensil scraps/kg	275.....(265)
Copper heavy scrap /kg	382.....(380)
Copper utensil scraps/kg	363.....(364)
Copper wire bar /kg	413.....(411)
Lead ingots /kg	138.....(135)
Nickel Cathodes /kg	895.....(880)
Tin slabs /kg	1110.....(1085)
Zinc slabs /kg	150.....(141)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	..............Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10292.....(10348)
DCH - 32 /Qtl	10798.....(10882)
Jaydhar /Qtl	9167.....(9251)
Shankar- 6 /Qtl	10601.....(10686)

Source:Cotton Association of India

Oil	..............Mumbai
Castor FSG /10kg	820.....(818)
Castor Comm /10kg	810.....(808)
Ricebran oil/10kg	820.....(-)
Groundnut oil /10kg	1280.....(1280)
Linseed oil /10kg	880.....(880)
Karanji /10kg	790.....(790)
Palm oil /10kg	728.....(724)
Sunflower exp ref /10kg	820.....(810)
Sunflower oil exp /10kg	740.....(725)
Soyabean ref / 10kg	778.....(760)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	..............Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3340-3552 .....(3336-3552)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	....
NYSE Crude	22.24.....(22.63)
Brent Crude (UK)	24.8.....(25.72)
Brent Crude (WTI)	22.43.....(22.43)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.55.....(1.6)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	171.62 .....(155.73)
Naptha spot /Rs/MT	-.....(45170)
LSHS spot/ M.T.	-.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	-.....(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	..............Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40556.....(41169)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40719.....(41335)
Silver.999/ kg	36850.....(37140)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18160.95	18141.00
Alumini-Mumbai (M)	1 K	137.60	137.60
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1602.50	1625.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1636.55	1638.35
Barley Jaipur (N)	1 Q	1700.00	1716.65
Castor Seed Disa (N)	1 Q	3880.20	3869.50
Castor Seed-Kadi (N)	X	3800.00	3857.50
Chana Bikaner (N)	1 Q	4021.00	4070.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4268.20	4300.00
Chana-Akola (N)	X	3985.00	4000.00
Coriander-Gondal (N)	X	5718.00	5700.00
Coriander-Jaipur (N)	X	5803.75	5800.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	5997.10	5997.30
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1826.75	1845.65
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1892.55	1908.35
Cotton-Kadi (N)	1 B	18035.00	18106.70
CPO-Kandla (M)	10 K	649.40	649.40
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	646.00	650.45
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	632.00	635.00
Gold Ahm (M)	10 G	40989.00	40989.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32923.00	32923.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4129.00	4129.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	5400.00	5457.80
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3450.00	3465.65
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1078.50	1085.10
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	14050.00	14200.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	13550.00	13655.55
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	787.75	790.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	971.50	970.25
Kapas-Rajkot (N)	X	967.70	967.30
Lead Mum (M)	1 K	141.60	141.60
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1535.00	1700.00
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	1700.00	1700.00
Maize-Erode (N)	X	1500.00	1500.00
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	1700.00	1700.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	1660.00	1670.00
Maize-Sangli (N)	X	1529.00	1527.25
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4637.50	4600.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7806.25	7818.75
Mustardseed Alwar (N)	20 K	3999.25	3999.25
Nickel Mumbai (M)	1 K	892.00	892.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	2975.00	2975.00
Paddy-Basmati-Pusa (N)	X	2787.50	2792.80
Pepper-Kochi (N)	1 Q	32527.25	32530.00
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	800.00	800.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1935.00	1940.00
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5234.25	5242.80
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	710.00	715.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	786.35	790.75
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	778.30	778.35
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	790.50	811.50
Rubber-Kochi (N)	1 Q	12775.00	12700.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	36871.00	36871.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	3692.00	3701.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	3550.00	3542.75
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	3711.75	3737.00
Soy Bean-Akola (N)	X	3465.00	3465.00
Soymeal Indore (N)	1 T	30000.00	30200.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3170.00	3170.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3285.70	3295.25
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3178.75	3180.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3380.95	3380.95
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3185.00	3227.50
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3100.00	3100.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5571.45	5587.50
Wheat Delhi (N)	1 Q	2155.00	2158.40
Wheat Kota (N)	1 Q	2000.00	2000.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	1850.00	1875.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	1970.00	2005.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	1765.00	1765.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5650.00	5650.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5000.00	4550.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	155.15	155.20

* as on Mar 20, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (सोमवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Mar 31	16480, 16570, 16310, 16310	3912	460	15638
Apr 30	16700, 16780, 16530, 16530	3869	439	19141
May 29	17090, 17090, 16810, 16960	26	6	2713
Jun 30	17200, 17200, 17200, 17200	04	1	264
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1809, 1834, 1779, 1824	34720	1787	59650
May 20	1840, 1847, 1801, 1844	15950	654	27360
Jun 19	1823, 1880, 1823, 1860	260	24	3770
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	960, 960, 933, 933	388	74	740
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	959, 960, 929, 929.5	656	417	2778
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Apr 20	3320, 3322, 3236, 3236	11305	955	48550
May 20	3280, 3318, 3246, 3276	2500	255	11700
Maize IndusNizamabad NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1300, 1319, 1300, 1319	40	4	360
May 20	1250, 1326, 1250, 1315	120	11	460
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Apr 20	3750, 3866, 3702, 3824	4800	588	17415
May 20	3658, 3824, 3658, 3804	2325	253	9755
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Mar 31	660, 688, 651.6, 667.4	20310	1344	19390
Apr 30	637, 662.2, 636, 651.4	20900	1410	44300
May 29	643.6, 661.9, 632, 648.6	4960	357	24740
Mentha Oil MCX(1 K)				
Mar 31	1152, 1178, 1130.4, 1130.4	51.84	100	105.48
Apr 30	1095.1, 1100, 1060.8, 1060.8	88.2	143	145.8
May 29	1075, 1075, 1042.7, 1046.9	2.88	8	11.16
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Apr 20	3975, 4117, 3970, 4103	8420	595	16450
May 20	3965, 4009, 3941, 3998	5750	405	15920
Jun 19	3961, 4001, 3957, 3974	310	27	2590
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Apr 20	764.8, 798, 764.8, 786.6	24205	2391	40500
May 20	745, 778, 745, 769.4	6935	845	9505
Jun 19	743, 751.6, 743, 750.8	95	11	665
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Apr 20	3510, 3658, 3508, 3652	21105	2016	112760
May 20	3492, 3648, 3492, 3632	11425	1460	63985
Jun 19	3548, 3662, 3540, 3636	3085	344	25810
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Apr 20	4948, 4948, 4897, 4899	3920	201	39315
May 20	4987, 4987, 4936, 4941	2670	146	11630
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Apr 20	3990, 4127, 3990, 4110	10660	813	21510
May 20	4000, 4076, 3976, 4062	6050	448	17400
Jun 19	4026, 4100, 4026, 4078	850	71	5530
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Apr 15	2116.4, 2116.4, 2116.4, 2116.4	0.1	1	4.5
May 15	2105.3, 2105.3, 2105.3, 2105.3	0.1	1	2.5
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	5810, 5998, 5753, 5884	2150	183	4750
May 20	5776, 5859, 5666, 5786	1000	74	3130
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Apr 20	13530, 13895, 13500, 13700	975	301	1929
May 20	13625, 13900, 13540, 13615	345	109	570
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Apr 20	5630, 5724, 5500, 5522	1355	215	4890
May 20	5656, 5716, 5510, 5532	725	111	1080
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
May 29	133.55, 134.4, 131.8, 133.3	8	5	6
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Mar 31	134.1, 134.1, 130.7, 132.1	4994	3963	3147
Apr 30	133.95, 134.3, 131.25, 133.4	1141	907	3040
Copper MCX(1 K)				
Mar 31	359.3, 360.7, 352.05, 355.95	12785	4598	5287.5
Apr 30	367, 367, 354.7, 361.55	3432.5	1257	2710
May 29	363, 389.95, 362.2, 371.7	7.5	3	40
Lead Mini MCX(1 K)				
Mar 31	129, 130, 124, 127.65	10157	7963	2799
Apr 30	130, 130.75, 124.3, 128.95	1310	1145	1685
Nickel MCX(1 K)				
Mar 31	848, 848, 823.3, 832.2	6453	3948	1306.5
Apr 30	828.8, 835.2, 821, 825.7	501	300	838.5
Zinc MCX(1 K)				
May 29	141.85, 142, 137.55, 140.6	65	51	76
Zinc Mini MCX(1 K)				
Mar 31	142, 144, 134.6, 141	22854	15761	7049
Apr 30	141.5, 141.5, 134.35, 139.45	6538	3854	8768
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40721, 40937, 39765, 40255	5.59	4787	5.48
Jun 05	40764, 41117, 40000, 40570	1.71	1471	13.68
Aug 05	41201, 41201, 41044, 41068	0.02	18	0.43
Gold Guinea MCX(8 G)				
Mar 31	33602, 34165, 33000, 33398	0.01	1231	0.01
Apr 30	33150, 33650, 32721, 32961	0.01	507	0.01
Gold Mini MCX(10 G)				
Apr 03	40668, 40970, 39820, 40270	1.79	15517	0.41
May 05	40600, 41015, 40011, 40449	0.22	1740	0.34
Jun 05	40936, 41080, 40000, 40484	0.03	224	0.05
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Mar 31	4000, 4009, 3930, 3964	0.01	2971	0.01
Apr 30	4015, 4035, 3961, 3980	0	1630	0.01
May 29	4098, 4098, 3980, 4034	0	91	0
Silver MCX(1 K)				
May 05	36409, 36758, 35700, 36356	264.21	7320	201.21
Jul 03	36606, 36968, 36164, 36803	5.55	181	8.46
Silver Micro MCX(1 K)				
Apr 30	36500, 38174, 36458, 37124	40.87	33901	20.46
Jun 30	36950, 38255, 36551, 37266	4.36	3467	4.39
Aug 31	37800, 38109, 37800, 37972	0	4	0.04
Silver Mini MCX(1 K)				
Apr 30	35500, 36822, 35490, 36398	123.35	21061	40.46
Jun 30	37000, 37250, 36400, 37011	1.82	336	4.06
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Mar 26	121.3, 121.3, 117, 118.7	45474mb	23685	19025mb
Apr 27	127.7, 128, 124.8, 126.7	5083mb	2756	4191mb
May 26	133.7, 134.5, 132.4, 134	134mb	107	453mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Apr 20	1905, 1905, 1746, 1759	11515bl	67017	2292bl
May 18	1992, 1992, 1919, 1933	200bl	1489	64bl
Jun 19	2097, 2097, 2097, 2097	0bl	1	1bl
सायं सत्र (शुक्रवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Mar 31	17380, 17400, 16860, 16980	8040	1092	17972
Apr 30	17530, 17650, 17120, 17210	7878	1052	17870
May 29	17820, 17890, 17440, 17510	1118	209	2696
Jun 30	17720, 17720, 17720, 17720	04	1	268
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	971, 978.5, 965, 971.5	372	65	740
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	970, 980, 963, 967.5	1348	802	2858
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Mar 31	657.6, 668, 636, 666.1	27160	2029	25070
Apr 30	642.4, 648, 620.2, 645.3	32290	2325	41370
May 29	642.7, 646.8, 619.8, 645.2	4860	426	22770
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Apr 20	757, 769.2, 749.2, 767.4	45160	4923	43170
May 20	736.8, 750.8, 730.2, 749	12985	1693	10345
Jun 19	728, 742.6, 722.4, 733.4	990	126	625
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
May 29	136.3, 136.3, 128.3, 134.1	10	10	7
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Mar 31	132.8, 137.15, 132.8, 134.75	16842	12713	2880
Apr 30	132.9, 135.85, 132.9, 134.55	1721	1421	2689
Copper MCX(1 K)				
Mar 31	369, 387, 363.25, 372.75	53635	19367	5455
Apr 30	369.65, 388.5, 366.5, 375	4072.5	1469	1552.5
Lead MCX(1 K)				
May 29	133.8, 136.25, 133.15, 135.75	26	10	25
Lead Mini MCX(1 K)				
Mar 31	133.6, 138.8, 129.1, 131.9	31453	24193	2159
Apr 30	132.1, 136.4, 130.2, 131.95	3471	2761	1425
Nickel MCX(1 K)				
Mar 31	860, 884.8, 852.3, 860.7	29704.5	18575	1030.5
Apr 30	858, 873.9, 847, 855	696	449	721.5
Zinc MCX(1 K)				
May 29	147.65, 149.75, 142.8, 143.25	162	129	71
Zinc Mini MCX(1 K)				
Mar 31	143, 150.6, 141.8, 143.15	67429	50053	6703
Apr 30	146.3, 150.45, 141.5, 142.5	7004	5401	6787
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	39900, 40948, 39838, 40358	15.28	13325	5.7
Jun 05	40004, 41066, 39892, 40393	2.74	2413	13.16
Aug 05	40340, 40653, 40310, 40604	0.05	48	0.42
Gold Guinea MCX(8 G)				
Mar 31	33275, 33798, 33202, 33552	0.03	2634	0.01
Apr 30	32725, 33525, 32700, 33065	0.01	845	0.01
May 29	32601, 33330, 32600, 32855	0	4	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Apr 03	40049, 40987, 39885, 40419	4.68	40952	0.37
May 05	40002, 40931, 39905, 40452	0.32	2645	0.35
Jun 05	40050, 40910, 39983, 40456	0.03	226	0.04
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Mar 31	3928, 4025, 3928, 3985	0.03	8481	0
Apr 30	3975, 4049, 3972, 3997	0.01	2838	0.01
May 29	4009, 4055, 3972, 4015	0	127	0
Silver MCX(1 K)				
May 05	35931, 37098, 35428, 35843	820.44	21582	226.11
Jul 03	36268, 37534, 35882, 36258	57.45	1721	8.28
Silver Micro MCX(1 K)				
Apr 30	36424, 37875, 36258, 36706	124.94	100291	19.91
Jun 30	36900, 38073, 36601, 37015	7.71	6400	4.51
Aug 31	37100, 38517, 37100, 37860	0.02	20	0.04
Nov 30	38624, 38624, 38624, 38624	0	1	0.01
Silver Mini MCX(1 K)				
Apr 30	36000, 37143, 35456, 35883	376.3	63709	41.69
Jun 30	36814, 37998, 36401, 36722	5.86	986	3.99
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Mar 26	122.1, 128.2, 121.1, 122.5	225034mb	126787	18360mb
Apr 27	129.3, 135.4, 127.6, 130.3	11410mb	7584	3774mb
May 26	135.3, 141.9, 135.3, 137.6	421mb	289	465mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Apr 20	2059, 2182, 1823, 1938	52238bl	323379	1827bl
May 18	2215, 2296, 1955, 2075	607bl	5072	61bl
Jun 19	2279, 2279, 2110, 2184	1bl	9	1bl
Jul 20	2369, 2369, 2321, 2337	0bl	2	0bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

देश के कई राज्यों में बंद का असर

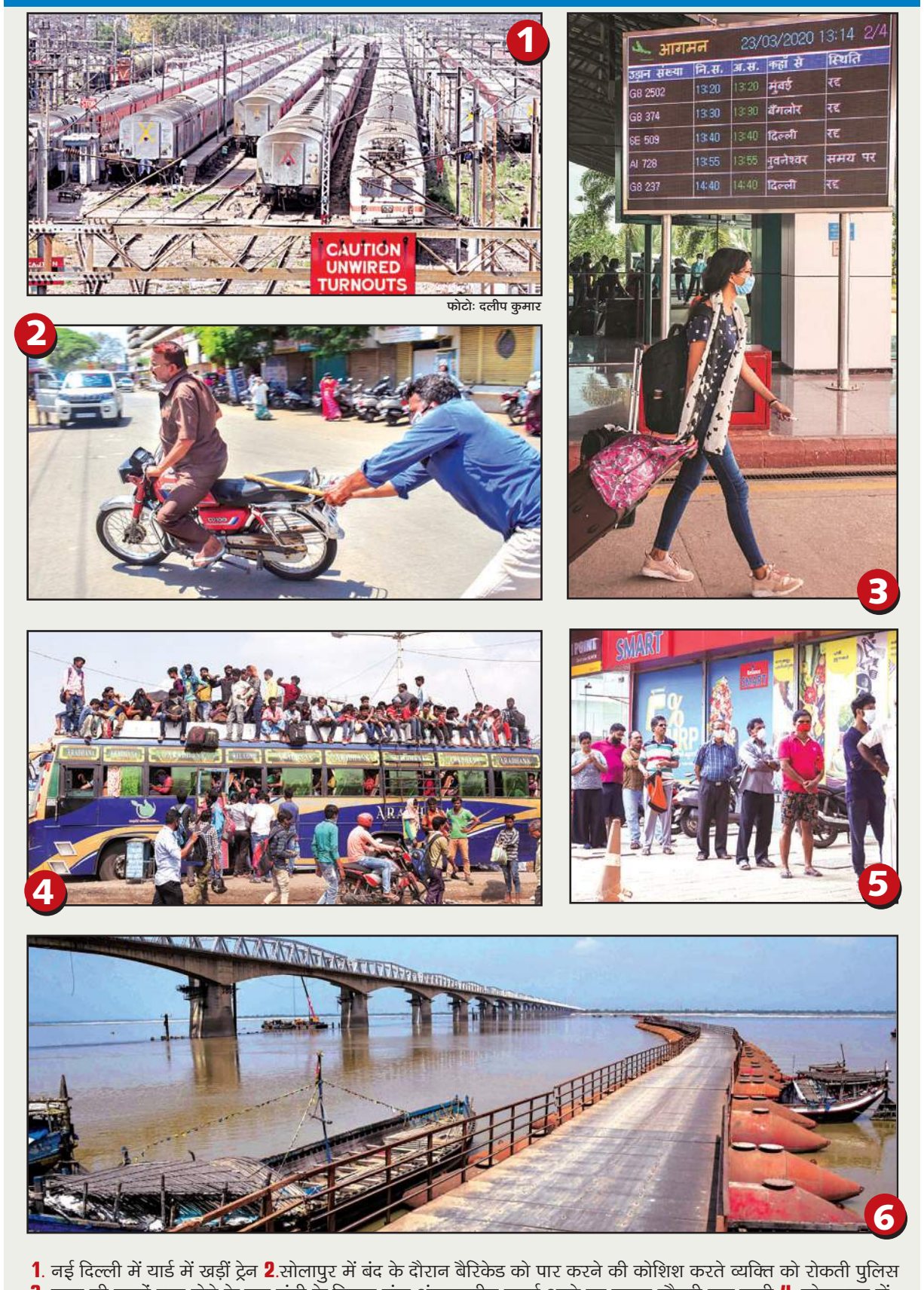

फोटो: दलीप कुमार

1. नई दिल्ली में यार्ड में खड़ीं ट्रेन **2**.सोलापुर में बंद के दौरान बैरिकेड को पार करने की कोशिश करते व्यक्ति को रोकती पुलिस **3**. बहुत सी उड़ानें रद्द होने के बाद रांची के बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस लौटती एक यात्री **4**. कोलकाता में लंबी दूरी की बस में यात्रियों की भीड़ **5**. कोरोनावायरस फैलने के कारण केरल में बंद के बाद कोझिकोड़ में रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए कतार में खड़े लोग **6**. पटना में सुनसान पड़ा महात्मा गांधी सेतु *(फोटो : पीटीआई)*

होटलों में वेतन कटौती!

कोरोनावायरस के चलते होटलों में आने वाले ग्राहकों की संख्या काफी कम हो गई है। रेटिंग एजेंसियों ने भी होटल कारोबार के अनुमानों में कटौती की

शैली सेठ मोहिले और श्रीपाद ऑटे

भारत कोरोनावायरस महामारी से लड़ने के लिए कई ठोस कदम उठा रहा है लेकिन इस बीच कई शहरों में होटलों के पूरी तरह बंद हो जाने तथा बाकी जगह ग्राहकों की संख्या में भारी कमी के चलते कई होटल मालिक शीर्ष तथा वरिष्ठ प्रबंधन के वेतन में कटौती पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल होटलों के लिए राहत की कोई खबर नहीं की है और इनमें से अधिकांश कारोबार के सामने आ रहे अभूतपूर्व संकट का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रीमियम श्रेणी के होटलों में घरेलू पेशेवरों की संख्या 76-77 प्रतिशत होती है और 23-24 प्रतिशत विदेशी नागरिक आते हैं।

हालांकि आवाजाही पर रोक तथा कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के बीच देशभर के होटलों में आने वाले लोगों की संख्या में चालू महीने में सालाना आधार पर 40 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। साथ ही, इक्रा का अनुमान है कि किसी एक महीने में होटल बुकिंग को रद्द कराने की संख्या अभी तक सबसे अधिक हो सकती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव करते हुए इसे स्थिर से बदलकर नकारात्मक कर दिया है।

फर्न होटल्स ऐंड रिसॉर्ट्स की तरह कई होटल उद्यमी इससे होने वाले नुकसान को नहीं सह सकते और उन्होंने वेतन कटौती की तलवार चला दी है। फर्न होटल्स ऐंड रिसॉर्ट्स के मुख्य परिचालन अधिकारी सुहैल कन्नमपिली ने कहा, अप्रैल महीने से हम वेतन में कटौती करने जा रहे हैं। हम शीर्ष प्रबंधन के वेतन में 50 फीसदी की कटौती से शुरुआत करते हुए इसे प्रबंधक के स्तर तक लाएंगे। कन्नमपिली ने बताया कि कंपनी के मुंबई स्थित तीन स्थानों को क्वारंटाइन केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और अगर इन तीनों को हटा दिया जाए तो कंपनी के शेष सभी 18 होटल बंद हो चुके हैं तथा होटल चेन का संचित घाटा वर्तमान में 35 करोड़ रुपये है। इक्रा ने आने वाले महीनों में होटल के कमरों की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगाया है लेकिन यह ग्राहकों की दरों में कमी के मुकाबले धीमी होगी।

कई दूसरी रेटिंग एजेंसियों ने भी होटल कारोबार में गिरावट का अनुमान लगाया है।

उद्योग पर आफत

- इक्रा ने होटल क्षेत्र की रेटिंग स्थिर से घटाकर नकारात्मक की
- फर्न होटल अगले महीने से शीर्ष तथा वरिष्ठ प्रबंधन के वेतन में करेगा कटौती
- विश्लेषण में बताया, अधिक कर्ज वाली कंपिनयों पर ज्यादा जोखिम
- देशभर में सालाना आधार पर होटल बुकिंग 40 प्रतिशत घटी

इंडिया रेटिंग्स का अनुमान है कि मार्च 2020 से शुरू होकर अगले 3 महीनों के दौरान मध्यम आकार या दो स्टार होटलों में ग्राहकों की संख्या में 30-40 फीसदी की गिरावट आएगी जबकि 4 स्टार या इससे ऊपर की श्रेणी वाले होटलों के ग्राहकों में 20-25 प्रतिशत की गिरावट आएगी।

यह ऐसे समय में है जब मॉनसून से पहले शादियों तथा छुट्टियों के चलते होटलों में बुकिंग की भरमार रहती थी। इसलिए इस समय होटल कारोबार में गिरावट का असर होटल कंपिनयों की पूरे साल की कमाई तथा प्रदर्शन पर पड़ेगा।

शैले होटल्स के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्याधिकारी संजय सेठी ने बताया कि कंपनी फिलहाल नौकरी या वेतन कटौती पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा, सभी को समय आने पर कदम उठाने पड़ेंगे। मुंबई, बेंगलूरु, हैदराबाद तथा पुणे शहरों में स्थित रेनेसां, मैरियट, वेस्टिन, नोवोल्ट जैसे प्रीमियम ब्रांड होटलों में आने वाले ग्राहकों की संख्या घट रही है।

प्रीमियम श्रेणी के होटलों के अतिथियों में 76-77 होते हैं घरेलू पेशेवर

सेठी कहते हैं, 'कारोबार की तरफ देखें तो किराए पर दी गई शैले की कुछ परिसंपत्तियां मदद कर रही हैं। इसने हमारे लिए जोखिम को कम कर दिया है। हम लागत कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन संबंधी पैसला सबसे बाद में लिया जाएगा। हमारा कर्मचारी-कमरा अनुपात हमेशा अच्छा रहा है।' शेरेटन ग्रांड, फोर प्वाइंट, हॉलिडे सहित विभिन्न ब्रांडों की संपत्ति का प्रबंधन करने वाली कंपनी ब्रिगेड हॉस्पिटैलिटी के कार्यकारी निदेशक विनीत वर्मा बताते हैं कि वेतन में कटौती फिलहाल हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है लेकिन अगर स्थित ऐसी हा बनी रहती है तो कंपनी इस विकल्प का भी उपयोग कर सकती है।

दिल्ली की कंपनी बना रही सस्ता वेंटिलेटर

सोहिनी दास

देश वैश्विक महामारी बन चुके कोरोनावायरस से जूझ रहा है। इसे मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की स्वास्थ्य तकनीक कंपनी अगवा हेल्थकेयर अगले 30 दिनों में 20,000 वेंटिलेटर बनाने के लिए रात-दिन काम कर रही है।

यह सस्ता वेंटिलेटर है, जिसे एक युवा रोबोटिक्स इंजीनियर और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान (एम्स) के एक डॉक्टर ने बनाया है। इसकी कीमत बाजार में उपलब्ध वेंटिलेटर की करीब 14 फीसदी है। देश में कुल चालू वेंटिलेटर करीब 40,000 होने का अनुमान है, जिसे देखते हुए कंपनी का लक्षित उत्पादन आंकड़ा काफी अधिक है। अगर कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हुई और केवल पांच फीसदी मरीजों को भी इंटेसिव केयर की जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं होगा।

एम्स के न्यूरोसर्जन डॉ. दीपक अग्रवाल और रोबोटिक्स वैज्ञानिक दिवाकर वैश ने यह सस्ता पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है। अगवा ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया है कि अगवा वेंटिलेटर का नाम इसे बनाने वालों के नाम पर रखा गया है। इसकी कीमत परंपरागत वेंटिलेटर की करीब 14 फीसदी है, जबकि इसमें परंपरागत वेंटिलेटर जैसी सभी खूबियां हैं। परंपरागत वेंटिलेटर की लागत करीब 10 लाख रुपये आती है।

कई बार कोशिशों के बाद भी वैश से तत्काल संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि उन्होंने रविवार को ट्वीट किया, 'वे अगले 30 दिनों में कम से कम 20,000 वेंटिलेटर बनाने के लिए रोजाना 24 घंटे काम कर रहे हैं।' कंपनी की वेबसाइट पर कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में वेंटिलेटर की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की वेबसाइट पर कहा गया है, 'बढ़ती मांग पूरी करने के लिए हमारी कंपनी में रोजाना 24 घंटे उत्पादन हो रहा है। उत्पादन का स्तर प्रत्येक सप्ताह में 1,000 यूनिट बढ़ा दिया गया है। आपूर्ति शृंखला में कई तरह के अवरोध आ रहे हैं। हालांकि हमने अपने पूरे परिचालन को दुरुस्त किया है। हमारा उत्पादन का मॉडल सबसे ताकतवर और किफायती है। यह कोविड-19 के मरीजों पर पूरी तरह से सही काम करता है। यह कदम समय और संसाधन बचाने के लिए उठाया जा रहा है।'

कंपनी विदेशी विनिर्माताओं के साथ साझेदारी के बारे में विचार कर रही है ताकि लाइसेंस के जरिये बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर का उत्पादन किया जा सके। अगवा ने अपनी वेबसाइट पर कहा, 'भारत ने देश में वेंटिलेटर की मांग में संभावित बढ़ोतरी को मद्देनजर रखते हुए उनके निर्यात पर रोक लगा दी है। इस वजह से हम अपने लाइसेंसों का इस्तेमाल कर प्रत्येक देश में स्थानीय विनिर्माताओं के साथ गठजोड़ कर बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार हैं।'

पंजाब, महाराष्ट्र में कर्फ्यू का ऐलान

पृष्ठ 1 का शेष

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं के अलावा कोई ढील नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे सहित कई शहरों में लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद भारी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। यह देखकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में अब तक कोरोनावायरस के 86 मामले सामने आ चुके हैं। ठाकरे ने कहा कि रविवार को राज्य की सीमाएं सील कर दी गई थीं और अब सभी जिलों की सीमाएं सील की जा रही हैं। मगर राज्य में दूध, बेकरी, किराना जैसे जरूरी सामान की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। राज्य सरकार ने बेस्ट की बसों और मुंबई लोकल को पूरी तरह बंद कर दिया है। चिंता की बात है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। यहां एक आईटी कंपनी ने अपनी महिला कर्मचारी को संक्रमित पाने पर पुणे की दो इमारतें खाली करा लीं। कंपनी ने यह भी कहा कि संक्रमित के संपर्क में आए लोगों को अलग रहने के लिए कहा गया है। कोरोनावायरस की यह महामारी तीसरे चरण में पहुंचती देखकर दिल्ली, झारखंड और नगालैंड को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने भी कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन के बीच सहायता पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी राशन कार्डधारक परिवारों को 1 महीने का राशन मुफ्त दिया जाएगा। नीतीश ने कहा कि सभी प्रकार के पेंशनधारकों को अगले तीन माह की पेंशन अग्रिम तौर पर तत्काल दी जाएगी।

कोविड-19 से दुनिया भर में अब तक 15,000 से अधिक की मौत

- दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की तादाद 3,37,500 और मृतकों की 15,000 से अधिक हो चुकी है।
- इटली में 5,476 लोगों की मौत के बाद रविवार को देश में आवाजाही पर रोक लगा दी गई
- ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर लोगों ने घुलने-मिलने से बचने की सलाह नहीं मानी तो आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
- जर्मनी में संक्रमित लोगों की संख्या 22,672 और मृतकों की 86 हो गई
- स्पेन में मरने वालों की संख्या 1,700 से अधिक होने के बाद आपातकाल को 11 अप्रैल तक बढ़ाने पर विचार
- ग्रीस ने रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की
- मोंटेनिग्रो में सोमवार को पहली मौत। पौलैंड ने कहा कि वह नागरिकों पर और प्रतिबंधों से इनकार नहीं कर सकता
- अमेरिका में लगभग हर तीन में से एक व्यक्ति बंदिशों के दायरे में आ गया है क्योंकि ओहाया, लुइसियाना, डेलवेयर और फिलाडेल्फिया में व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं
- राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 16 मार्च को जारी 15 दिन की योजना समाप्त होने के बाद अलगे कदमों के बारे में फैसला लेगा
- कनाडा में रविवार को मृतकों की तादाद 50 फीसदी बढ़ी। अधिकारियों ने एहतियात नहीं बरतने वालों को दंडित करने की चेतावनी दी
- ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोलसोनारो ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान को खारिज किया कि अगले महीने स्वास्थ्य प्रणाली नाकाम हो जाएगी। वहां मृतकों की संख्या में 39 फीसदी और पुष्ट मामले 1,500 का आंकड़ा कर चुके हैं पार
- पनामा में नए मामलों में 28 फीसदी बढ़ोतरी, जिससे कुल संख्या 313 हो गई
- ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को पब, क्लब, जिम और पूजा स्थल बंद किए। देश में कोरोनावायरस के मामले 1,600 से अधिक हुए। प्रशासन ने एक यात्री जहाज के प्रवेश पर रोक लगाया, जिसमें सवार सैकड़ों लोग श्वास से संबंधित बीमारी की शिकायत कर रहे हैं।
- चीन में लगातार चार दिन से बढ़ रहे दैनिक मामलों में गिरावट आई। चीनी प्रशासन ने आयातित संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध और कड़े किए हैं।
- दक्षिण कोरिया में सोमवार को 29 फरवरी के बाद सबसे कम नए मामले आए। मामलों में गिरावट के रुझान से उम्मीद जगी है कि यह महामारी काबू में आ सकती है।
- इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में दो सप्ताह की आपात अवधि की शुरुआत में सोमवार को सिनेमा और अन्य सार्वजनिक मनोरंजन पर रोक लगाई गई
- ईरान के राष्ट्रपति ने सोमवार को कहा कि अगर अमेरिका उनके देश की मदद करना चाहता है तो उसे सबसे पहले प्रतिबंध हटाने चाहिए।

ओटीटी पर अभी नहीं होगा एचडी प्रसारण

सीओएआई ने 11 वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनियों से बैंडविड्थ की उपयोगिता घटाने को कहा था ताकि दूरसंचार नेटवर्क पर दबाव न आए

सुरजीत दास गुप्ता

कुछ समय के लिए आपको हाई डेफिनिशन पर फिल्म न देखने के लिए तैयार रहना होगा अथवा आपको अपने पसंदीदा ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड या स्ट्रीमिंग करते समय कम स्पीड जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने 11 वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनियों से बैंडविड्थ की उपयोगिता घटाने का आह्वान किया था ताकि दूरसंचार नेटवर्क पर अधिक दबाव न आए। इसी क्रम में डिज्नी के हॉटस्टार, ज़ी5 एवं वायकॉम18 द्वारा परिचालित वूट ओटीटी ने बिट दरों को पहले ही कम करने का निर्णय लिया है।

दूरसंचार कंपनियों के इस संगठन ने कुछ दिनों पहले अपने पत्र में ओटीटी सेवा प्रदाताओं को विज्ञापन और पॉप अप को हटाने के लिए कहा था जो आमतौर पर उच्च बैंडविड्थ की खपत करते हैं। साथ ही उन्हें अस्थायी तौर पर एचडी स्ट्रीमिंग के बजाय एसडी के लिए पहल करने का आग्रह किया था। सीओएआई ने 11 से अधिक स्ट्रीमिंग सेवा कंपनियों को पत्र इस संबंध में पत्र लिखा है जिनमें हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, एमेजॉन प्राइम, ज़ी5, वूट, ऑल्ट बालाजी, सोनी लाइव आदि शामिल हैं। साथ ही सीओएआई ने दूरसंचार विभाग से भी अनुरोध किया है कि इसके लिए ओटीटी कंपनियों को निर्देश दिया जाए।

दूरसंचार कंपनियों ने कहा है उनके नेटवर्क पर मांग में अचानक 10 फीसदी से अधिक की तेजी आई है क्योंकि अधिक से अधिक लोग घर से काम कर रहे हैं अथवा शहरों को लॉकडाउन किए जाने के कारण वे घर पर हैं।

सबसे बड़ी ओटीटी कंपनी हॉटस्टार के प्रवक्ता ने कहा, 'हम इस असाधारण परिस्थिति के प्रति सचेत हैं और उस पर करीबी नजर रख रहे हैं। ग्राहक और देश के व्यापक हित में हम लगातार बदलाव करने और एचडी स्ट्रीमिंग की बिट दरों में कमी करने के लिए तैयार हैं।' हॉटस्टार के ग्राहकों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है।

कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी वीडियो स्ट्रीमिंग बिट दरों को स्वत: अनुकूलित करती है जिससे इंटरनेट की कम खपत सुनिश्चित होती है, इसलिए वह सामग्री की जटिलता- जैसे मनोरंजन बनाम लाइव स्पोर्ट्स के आधार पर एन्कोडिंग का अनुकूलन करते हैं। डिज्नी ओटीटी ने यह भी बताया कि एचडी विकल्प केवल भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध है जबकि उसके 30 करोड़ उपयोगकर्ताओं में से अधिकतर एसडी देखते हैं।

यहां तक कि ज़ी5 भी इस चुनौती से निपट रही है। ज़ी5 के सीईओ तरुण कात्याल ने कहा, 'हम भारतीय दर्शकों के डेटा खपत पैटर्न को समझते हैं। हम किसी भी डिवाइस पर स्ट्रीमिंग को डिलिवर करने पर पाबंदी लगाने के लिए उपाय कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मौजूदा बैंडविड्थ खत्म नहीं हुआ है।' उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में सीओएआई के साथ करीबी से काम कर रहे हैं।

ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इंटरनेट की खपत कम करने के लिए बिट दरें घटाने का फैसला लिया

प्रतिस्पर्धी कंपनी वायकॉम18 डिजिटल वेंचर्स के सीओओ गौरव रक्षित ने कहा कि वूट एकसमान स्ट्रीमिंग करती है। उन्होंने कहा, 'वूट सिलेक्ट प्लेटफॉर्म (सब्सक्रिप्शन) पर हमारे उपयोगकर्ताओं की संख्या काफी कम है और वे अपनी बढ़ी हुई खपत के मद्देनजर एसडी के लिए भी तैयार हैं।' वूट के ग्राहकों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है।

हालांकि इस क्षेत्र की बड़ी कंपनी नेटफ्लिक्स ने अपनी योजना के बारे में कोई भी टिप्पणी या खंडन करने से इनकार करते हुए केवल इतना कहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर कोई विज्ञापन नहीं है। कंपनी अपने ग्राहकों को एसडी और एचडी दोनों विकल्प उपलब्ध कराती है।

हालांकि वह यूरोप में बैंडविड्थ के उपयोग पहले ही 25 घटा चुकी है। साथ ही उसके पास ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे इस कमी के बावजूद एचडी उपयोगकर्ताओं के लिए सेवा की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता।

सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने कहा, 'हमारी नेटवर्क क्षमता में वीडियो स्ट्रीमिंग की हिस्सेदारी 30 से 35 फीसदी है। अगर हम एचडी से एसडी की ओर रुख कर लें तो बैंडविड्थ की उपयोगिता में 20 से 30 फीसदी की कमी लाई जा सकती है क्योंकि कई ग्राहकों इसके जरिये टीवी प्रसारण चैनलों की स्ट्रीमिंग भी करते हैं। यदि विज्ञापन को भी बंद कर दिया जाता है तो इससे राजस्व का नुकसान हो सकता है लेकिन इससे टीएसपी को डेटा में बढ़ते उछाल से निपटने में मदद मिलेगी।'